@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

आईने के सामने खुद को देख रो पड़ती थीं अविका

...पेज-8

नई दिल्ली, मंगलवार, 30 जून 2026, वर्ष-1, अंक-221, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, आसमान नहीं टूट पड़ेगा ...इतनी क्या जल्दी है

राम मंदिर चढ़वा चोरी मामले में तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के अनुरोध वाली याचिका पर त्वरित सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायाधीश शील नागू की पीठ ने कहा कि इस मामले को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

पीठ ने मौखिक टिप्पणी की, आसमान नहीं टूट पड़ेगा ...इतनी क्या जल्दी है।

अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के नेतृत्व वाले एक बहु-विषयक विशेष जांच दल (एसआईटी) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मामलों और प्रशासन से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं व अन्य कथित अवैधताओं की जांच करनी चाहिए।

इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली याचिका में केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और मंदिर ट्रस्ट को सार्वजनिक हित की रक्षा करने तथा करोड़ों भक्तों व दानदाताओं का विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक नियामक, पर्यवेक्षी और ऑडिट तंत्र का गठन व संचालन करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े धन के कथित गबन और अन्य कथित अनियमितताओं की खबरें सही साबित हों या नहीं, लेकिन इन खबरों ने उन पीढ़ियों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है, जिन्होंने अयोध्या की गौरवपूर्ण विरासत की पुनर्स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया है।

इसमें आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बिना किसी प्राथमिकी या नियमित आपराधिक मामला दर्ज किए इस मामले की जांच शुरू कर दी है। याचिका में कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट से कथित रूप से धन गायब होने और अन्य कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित रिपोर्टों की सत्यता की स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए। याचिका के अनुसार, यह जांच ऐसी एकीकृत जांच एजेंसी द्वारा कराई जानी चाहिए, जिसके पास जटिल वित्तीय और आपराधिक मामलों की जांच के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, संसाधन और संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध हो। इसमें कहा गया है, ऐसी जांच से आम लोगों का भरोसा अधिक मजबूत होगा, बजाय इसके कि केवल प्रशासनिक अधिकारियों वाली विशेष जांच टीम (एसआईटी) प्रारंभिक जांच करे, जिनके पास आपराधिक मामलों की जांच की विशेषज्ञता शायद नहीं हो।

राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन के आरोपों के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था।

इस विशेष जांच दल (एसआईटी) में लखनऊ के मंडल आयुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल है।

14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरोपी

अयोध्या,एजेंसी। राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों को सोमवार को अयोध्या की एक अदालत में पेश किया गया। आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में सभी आरोपियों को अब 13 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अभी कई पहलुओं से जांच की जानी है, ऐसे में आरोपियों को न्यायिक हिरासत में रखना जरूरी है। पुलिस ने पहले ही कहा था कि फिलहाल वह उनकी हिरासत नहीं मांगेगी, बल्कि जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ के लिए प्रश्नों की विस्तृत सूची तैयार करने के बाद आने वाले दिनों में हिरासत में लेगी।

त्रि-भाषा नीति दसवीं के मौजूदा सत्र पर लागू नहीं: सीबीएसई

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप त्रि-भाषा नीति को लागू करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से दिशा-निर्देश जारी किये हैं। सीबीएसई ने आज दिशा-निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10 के छात्रों पर नयी व्यवस्था लागू नहीं होगी और वह पहले की तरह केवल दो भाषाओं के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे। कक्षा 9 के सभी छात्रों को अब तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। यदि कोई छात्र पहले से दो भारतीय भाषाएं पढ़ रहा है, तो वह तीसरी भाषा के रूप में किसी अन्य भारतीय भाषा या अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन जैसी विदेशी भाषा का चयन कर सकता है। वहीं, जो छात्र एक भारतीय और एक विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं।

उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा चुननी होगी। जिन छात्रों ने पहले से दो विदेशी भाषाएं ले रखी हैं, उन्हें एक बार की विशेष छूट के तहत केवल एक अतिरिक्त भारतीय भाषा जोड़नी होगी। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि कक्षा 9, 7 और 8 के वर्तमान बैच के लिए तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक परीक्षा के माध्यम से होगा। इन छात्रों को कक्षा 10 में पहुंचने पर तीसरी भाषा की सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं, वर्ष 2026-27 में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले और उसके बाद के सभी बैचों को कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देनी होगी।

छात्रों की सहायता के लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी स्तरानुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराएंगे। सीबीएसई ने दिव्यांग छात्रों, विदेश स्थित सीबीएसई स्कूलों तथा विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों को त्रि-भाषा नीति से कुछ छूट भी प्रदान की है। साथ ही दूसरे राज्यों में स्थानांतरित होने वाले परिवारों के बच्चों को अपनी पूर्व भाषा व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी गई है। बोर्ड ने स्कूलों को आवश्यक शिक्षकों की व्यवस्था, अंतर-विद्यालय सहयोग और वर्चुअल शिक्षण जैसे विकल्प अपनाने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई ने कहा कि नयी व्यवस्था का उद्देश्य परीक्षा का बोझ बढ़ाना नहीं हैं।

एक जुलाई से हटेंगे पेट्रोल-डीजल बिक्री पर लगे सभी अस्थायी प्रतिबंध

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री एवं वितरण पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) की बिक्री पर लागू अस्थायी नियामक उपाय समाप्त कर दिए जाएंगे।

सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में पैदा हुए भू-राजनीतिक संकट के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई थी। इसके बावजूद सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों को स्थिर बनाए रखा।

शहीदों का अपमान करने के लिए इस्तीफा दें राजनाथ : कांग्रेस

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के विषय में संसद में झूठ बोलकर शहीदों का अपमान किया है और ऐसे में उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए। पार्टी के 'पूर्व सैनिक विभाग' के प्रमुख कर्नल (सेवानिवृत्त) रोहित चौधरी ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा को जनता से माफी मांगनी चाहिए।

मई 2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हुए छह सैन्यकर्मियों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक की एक दीवार पर अंकित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस

अभियान के बाद पहली बार सरकार ने छह शहीद सैन्यकर्मियों के नाम आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किए हैं। चौधरी ने राजनाथ सिंह द्वारा पिछले साल जुलाई में संसद में दिए गए एक वक्तव्य का हवाला देते हुए संवाददाताओं से कहा, मोदी सरकार की बुनियाद झूठ पर टिकी है, उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। देश पूछ रहा है कि हमारे शहीद जवानों के नाम सामने आने में 13 महीने क्यों लग गए? यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है।

सार समाचार

भारत और ग्रीस के बीच नई तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली,एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि उन्होंने ग्रीस के विकास मंत्री टाकिस थियोडोरिकाकोस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें भारत और ग्रीस के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, हमने मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और उभरती हुई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की, ताकि दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

असम में भारी बारिश और बाढ़ के बीच भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन

गुवाहाटी,एजेंसी। भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के तहत स्पीयर हेड डिवीजन के जवानों ने सोमवार को असम के धेमाजी जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से 27 फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह राहत और बचाव अभियान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और जिला प्रशासन के साथ मिलकर चलाया गया। सेना के अनुसार, यह बचाव अभियान धेमाजी जिले के अरुण चापोरी गांव में चलाया गया, जहां लगातार बारिश और अचानक पानी का स्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए और लोग फंस गए थे। आपात स्थिति की सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे और खराब मौसम तथा कठिन परिस्थितियों के बावजूद राहत कार्य शुरू किया। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।

कोलकाता में टीएमसी नेताओं पर एफआईआर

कोलकाता,एजेंसी। ट्रैफिक बाधित करने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता कुणाल घोष, डोला सेन और बैसवानर चट्टोपाध्याय के खिलाफ सोमवार को हरे स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के अनुसार, रविवार को ये टीएमसी नेता कोलकाता के सेंट्रल इलाके एस्प्लेनेड में विक्टोरिया हाउस के सामने सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे, ताकि पार्टी के 21 जुलाई के शहीद दिवस कार्यक्रम के लिए मंच लगाने की तैयारी की जा सके। इस दौरान सड़क पर भीड़ और गतिविधियों के कारण पीक आवर्स में यातायात बाधित हुआ और आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

राज्यसभा के आठ नवनिर्वाचित सदस्यों ने ली शपथ, खरगे फिर बने नेता प्रतिपक्ष

नई दिल्ली, एजेंसी।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत आठ नवनिर्वाचित सदस्यों ने सोमवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इसी के साथ, खरगे को फिर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी गई। राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने नए सदस्यों को शपथ दिलाई।

खरगे ने राधाकृष्णन के कक्ष में अलग से शपथ ली, जबकि अन्य सात सदस्यों ने राज्यसभा कक्ष में शपथ ग्रहण की। खरगे और भाजपा नेता तरुण चुघ के अलावा शपथ लेने वाले नए सदस्यों में गुजरात से जितेंद्र मेघजीभाई कंजारिया और मानसिंह मेरामन परमार, कर्नाटक से एम. नागराजा, महाराष्ट्र से राजेंद्र हीरालाल जैन, मणिपुर से अधिकारीमयुम शारदा देवी तथा राजस्थान से अलका सिंह शामिल हैं। शपथ ग्रहण के दौरान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद थे। वे सभापति के कक्ष और सदन, दोनों स्थानों पर मौजूद रहे। खरगे ने हाथ में संविधान की प्रति लेकर हिंदी में शपथ ली। उनके शपथ लेने के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा भी मौजूद थीं। राधाकृष्णन ने नए सदस्यों को बधाई दी और उच्च सदन में उनका स्वागत किया।

सेशेल्स यात्रा कई ठोस और महत्वपूर्ण परिणामों से भरपूर: मोदी

विक्टोरिया, एजेंसी।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशेल्स की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हुए। इस दौरे को पीएम मोदी ने ठोस और महत्वपूर्ण परिणामों से भरपूर बताया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सफल यात्रा की झलक दिखाई। एक वीडियो क्लिप पोस्ट करते हुए लिखा, ₹सेशेल्स की मेरी यात्रा कई ठोस और महत्वपूर्ण परिणामों से भरपूर रही है, जो भारत और सेशेल्स की मित्रता को और अधिक मजबूत बनाएगी।

प्रधानमंत्री ने बीते 50 साल की नींव को आगामी 50 साल की समृद्धि के लिए अहम माना। उन्होंने आगे लिखा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले पचास वर्षों में हमारे संबंध गहरे भरोसे और साझा प्रगति की नींव पर खड़े रहे हैं। आने वाला अगला पचास वर्ष नवाचार,

सतत विकास और साझा समृद्धि से परिभाषित होगा। भारत के पीएम ने यकीन के साथ कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी यह यात्रा सेशेल्स-यूरोपीय संघ (ईयू) संबंधों को भी बेहतर बनाने में मददगार रही है, जिनमें ठोस परिणाम सामने आए हैं। पीएम मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा, मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि मुझे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का अवसर मिला, खासकर ऐसे समय में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है। मैं राष्ट्रपति हर्मिनी, सेशेल्स की सरकार, वहां की जनता और सेशेल्स के लोगों के स्नेह और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

बता दें कि पीएम मोदी सेशेल्स के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। सेशेल्स की आजादी और भारत-सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 साल भी पूरे हुए हैं। उपलब्धियों और परिणामों की बात करें तो भारत और सेशेल्स ने 19 अहम समझौतों और घोषणाओं का ऐलान किया। इसमें प्रत्यर्पण संधि, यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान शुरू करने, डिजिटल भुगतान आदि शामिल है।

सेशेल्स दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी ने पीस पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए और उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोगों से भी बात की। तिरंगा लिए हुए भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए 'मोदी-मोदी' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाए। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी कई तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, विक्टोरिया के पीस पार्क में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

बापू के आदर्श पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जो लोगों को शांति, न्याय और इंसानी सम्मान की तलाश में एकजुट करते हैं। उनके विचार एक बेहतर दुनिया के लिए हमारी मिलकर की जाने वाली कोशिशों को प्रेरित करते रहते हैं।

नड्डा ने नए सिरे से तैयार 'एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) अभियान' के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए

स्वास्थ्य 'विकसित भारत 2047' की आधारशिला : नड्डा

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने सोमवार को कहा कि स्वास्थ्य 'विकसित भारत 2047' की आधारशिला है और भारत की स्वास्थ्य क्षेत्र की सफलता की कहानी में राज्य बराबर के भागीदार हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मामलों की केंद्रीय परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए नड्डा ने कहा, चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है; इसलिए स्वास्थ्य क्षेत्र की हर उपलब्धि में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समान भूमिका है।

उन्होंने कहा, हालांकि केंद्र सरकार नीतिगत मार्गदर्शन, तकनीकी सहायता और वित्तीय मदद देती है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक लागू करना राज्यों की प्रतिबद्धता और सक्रिय प्रयासों पर निर्भर करता है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने 2047 तक 'विकसित भारत' बनने का लक्ष्य रखा है, जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा।

उन्होंने कहा, स्वस्थ भारत के बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता और स्वास्थ्य राष्ट्रीय विकास के सबसे अहम स्तंभों में से एक बना हुआ है। स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मातृ मृत्यु दर 2014 में प्रति एक लाख बच्चों के जन्म पर 130 के आंकड़े से घटकर अब 87 रह गई है। संयुक्त राष्ट्र की 'मातृ मृत्यु दर अनुमान रिपोर्ट 2024' का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर में 48 प्रतिशत की कमी के मुकाबले भारत में इसमें 86 प्रतिशत की कमी आई है।

उन्होंने कहा कि 1990 के बाद से भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 79 प्रतिशत और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में 70 प्रतिशत की कमी आई है; साथ ही, कुल प्रजनन दर 2.0 तक पहुँच गई है और औसत आयु बढ़कर 70.3 साल हो गई है। नड्डा ने नए सिरे से तैयार 'एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) अभियान' के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए। जीवन की शुरुआती अवस्था से ही एनीमिया की समस्या से निपटने के महत्व को समझते हुए, इस अभियान में 0-6 महीने की उम्र के कम वजन वाले शिशुओं को सातवें लाभार्थी समूह के तौर पर शामिल किया गया है।

श्री अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत, उप-राज्यपाल ने की 'प्रथम पूजा'

श्रीनगर, एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा में 'प्रथम पूजा' की, जिसके साथ ही सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हुई यह पवित्र रस्म यात्रा की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है।

वहीं, जम्मू में अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पहली पूजा-अर्चना ज्येष्ठ पूर्णिमा पर तवी नदी के किनारे की गई। यह समारोह महामंडलेश्वर महंत रामेश्वर दास की मौजूदगी में आयोजित किया गया और इसमें जम्मू के डिप्टी कमिश्नर दिनेश चंद्र और स्थानीय विधायकों समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए मंगलवार को सुरक्षा इंतजामों, गाड़ियों के काफिले की आवाजाही और यात्रा से जुड़ी कुल तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक 'ड्राई रन' (अभ्यास) किया गया। इस ट्रायल काफिले को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया और यह जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे से होते हुए उधमपुर से बनिहाल की ओर बढ़ा। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और आईजीपी जम्मू भीम सेन तुती समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही सिविल प्रशासन, पुलिस, सीआरपीएफ, सेना और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी इस अभ्यास में शामिल हुए और इंतजामों की निगरानी की। सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की व्यापक तैयारी के तहत रामबन से यात्रा के लिए 'ड्राई कॉन्वॉय रिहर्सल' (बिना यात्रियों के काफिले का अभ्यास) किया गया।

झारखंड-दिल्ली से चल रहे साइबर ठगी गैंग पर पुलिस का शिकंजा, 10 गिरफ्तार

आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की गई

नई दिल्ली,एजेंसी।

दक्षिण-पश्चिम जिला साइबर पुलिस ने अंतरराज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह झारखंड के जामताड़ा, देवघर और दिल्ली-एनसीआर से संचालित हो रहा था। आरोपियों के कब्जे से 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, डिजिटल साक्ष्य और ठगी की रकम से खरीदी गई एक महिंद्रा थार रॉक्स कार बरामद की गई है। पुलिस ने 26 लाख रुपये से अधिक की साइबर ठगी से जुड़े चार मामलों का खुलासा करने का दावा किया है।

दक्षिण-पश्चिम जिले के पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि साइबर सेल एक जैसे तरीके से अंजाम दिए गए चार मामलों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान गिरोह के तार झारखंड के जामताड़ा और देवघर से जुड़े मिले। इसके बाद अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को बैंक अधिकारी, बीएसईएस कर्मचारी या अन्य सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद व्हाट्सएप पर फर्जी एपीके फाइल भेजी जाती थी।

फाइल इंस्टॉल होते ही मोबाइल हैक हो जाता था और आरोपी इंटरनेट बैंकिंग, ओटीपी सहित अन्य संवेदनशील जानकारियां हासिल कर पीड़ितों के खातों से रकम निकाल लेते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों और ठगी के नेटवर्क की जांच कर रही है। पहले मामले में एक वरिष्ठ नागरिक को सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का झांसा देकर 18.50 लाख रुपये की ठगी की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा और देवघर से मुख्य आरोपी मंजूर आलम समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया।

इनमें बुलंदशहर निवासी यूसुफ तथा मेरठ निवासी आर्यन, राम प्रकाश, मनोहर और प्रियदर्शन शामिल हैं। इनके पास से एक महिंद्रा थार रॉक्स कार, छह मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। दूसरे मामले में क्रेडिट कार्ड की केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 1.01 लाख रुपये ठग लिए गए। इस मामले में देवघर निवासी रविंद्र कुमार मंडल को हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से तीन मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद हुआ।

तीसरे मामले में पीड़ित को एम-परिवहन चालान के नाम से एपीके फाइल भेजकर उसका मोबाइल हैक किया गया और 1.09 लाख रुपये की ठगी कर ली गई। इस मामले में पुलिस ने देवघर से राम विजय कुमार दास को गिरफ्तार कर उसके पास से तीन मोबाइल फोन बरामद किए।

चौथे मामले में खुद को बीएसईएस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से 6.31 लाख रुपये की ठगी की गई थी। पुलिस ने इस मामले में हजारीबाग निवासी अंकित कुमार और गिरिडीह निवासी गोलू कुमार को गिरफ्तार किया।

विदेशी महिला से देह व्यापार कराने का भंडाफोड़

गाजियाबाद, एजेंसी।

न्यू गांधीनगर स्थित किराये के मकान में विदेशी महिला से अनैतिक देह व्यापार कराने वाले आरोपी को सिहानी गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से विदेशी महिला को रेस्क्यू कर सुरक्षित संरक्षण में भेज दिया है। जांच में सामने आया कि आरोपी पूर्व में भी अनैतिक देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि रविवार रात सिहानी गेट पुलिस को सूचना मिली थी कि न्यू गांधीनगर स्थित एक मकान में अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने सूचना के साथ मौके के फोटो और वीडियो भी उपलब्ध कराए थे।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए वह खुद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने एक विदेशी महिला को रेस्क्यू किया, जबकि मकान से धंधा संचालित कर रहे नेहरू नगर द्वितीय निवासी अंकित गुप्ता उर्फ राहुल मलिक को गिरफ्तार किया। एसीपी ने बताया कि महिला को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद सुरक्षित संरक्षण में भेजा गया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह आर्थिक लाभ और घर का खर्च चलाने के लिए किराये के मकानों में देह व्यापार संचालित करता था।

उसने विदेशी महिला को बहलाकर बुलाया था। एसीपी के मुताबिक, अंकित गुप्ता ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर महिलाओं की तस्वीरें लगाता था। इच्छुक लोगों से संपर्क होने पर उन्हें तय स्थान पर बुलाकर सौदा कराया जाता था। एसीपी का कहना है कि आरोपी के मोबाइल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अंकित गुप्ता के खिलाफ सिहानी गेट थाने में पहले भी देह व्यापार कराने का मुकदमा दर्ज है। उस मामले में वह गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुका है। आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत, सीमा विवाद में उलझी पुलिस

दादरी, एजेंसी।

जारचा कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर सैंथली मोड़ पुलिस चौकी के समीप ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस सीमा विवाद में उलझ गई जिससे नाराज होकर परिजनों व ग्रामीणों ने जीटी रोड पर जाम लगा दिया। करीब एक घंटा जाम लगने के बाद सीमा विवाद सुलझने पर जाम खुलवाया गया। घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में लगी है। बुलंदशहर के अकत्यार पुर गांव निवासी प्रदीप (27) परिवार के साथ रहते थे। वह शनिवार की रात्रि बाइक से अपने गांव से दादरी जा रहे थे।

जब वह जीटी रोड स्थित सैंथली मोड़ पुलिस चौकी के समीप पहुंचे तो ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सिकंदराबाद स्थित अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घटना की सूचना परिजनों को दी गई। सूचना पाकर परिजन व ग्रामीण भी पहुंच गए। जब परिजनों ने पुलिस कार्रवाई करने को कहा तो जारचा पुलिस ने सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र का मामला बताकर सिकंदराबाद भेज दिया जबकि सिकंदराबाद से मामला जारचा कोतवाली क्षेत्र का बताकर लौटा दिया। इससे परेशान होकर परिजन व ग्रामीण ने शव को घटना स्थल सड़क पर रखकर जाम लगा दिया।

सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। ग्रामीण कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े रहे। करीब एक घंटे तक जाम लगने के बाद सीमा विवाद सुलझा।

मामला जारचा कोतवाली क्षेत्र में निश्चित किया गया। जारचा कोतवाली में ट्रक नंबर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश में लगी है। एसीपी प्रशाली गंगवार का कहना है कि समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया। रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

घरों-दुकानों के शटर तोड़कर चोरी के आरोप में सात गिरफ्तार

गुरुग्राम, एजेंसी।

मेडिकल स्टोर समेत घरों और दुकानों के ताले-शटर तोड़कर चोरी करने वाले संगठित गिरोह के सात आरोपियों को अपराध शाखा फरुखनगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले रेकी करते थे, फिर रात में वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने सोमवार को बताया कि पूछताछ में गिरोह ने गुरुग्राम में पांच और दिल्ली में एक समेत कुल छह चोरियों का खुलासा किया है। 25 जून 2026 को वजीरपुर रोड, सुल्तानपुर मोड़ फरुखनगर स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालक ने थाना फरुखनगर में शिकायत दी थी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 24/25 जून की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी दुकान का शटर तोड़कर गल्ले से करीब 20,000 रुपये चोरी कर लिए। केस दर्ज कर अपराध शाखा फरुखनगर ने जांच शुरू की।पुलिस टीम ने गांव खेड़ा झाड़रौला गुरुग्राम से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान तारुल निवासी सुल्तानपुरी दिल्ली, सोनू निवासी शाहबाद दौलतपुर दिल्ली, मेराजुल दीवान निवासी बवाना दिल्ली, संजीत काली निवासी शाहबाद डेयरी दिल्ली, मनदीप स्कूटी निवासी शाहबाद दौलतपुर दिल्ली, प्रह्लाद कुमार राज कुमार मोटा निवासी सेक्टर-26 रोहिणी दिल्ली तथा सात सागर निवासी रोहिणी दिल्ली के रूप में हुई है।

पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और आदतन चोरी करते हैं। गिरोह पहले घरों और दुकानों की रेकी करता था। यह सुनिश्चित करता था कि वहां कोई मौजूद न हो। फिर रात में ताले या शटर तोडक़र नकदी और कीमती सामान चोरी कर लेते थे। मेडिकल स्टोर में भी रेकी के बाद ही शटर तोडक़र गल्ले से नकदी चुराई गई।

पूछताछ में आरोपियों ने गुरुग्राम में पांच अन्य जगहों और दिल्ली में एक जगह चोरी करना कबूला है। इस तरह गिरोह ने कुल छह वारदातों का खुलासा किया है।

पुलिस इन सभी मामलों में आगे जांच और बरामदगी कर रही है। आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आरोपी तारुल पर चोरी, नकबजनी, लूट व आर्म्स एक्ट के 15 केस, मनदीप उर्फ स्कूटी पर चोरी व नकबजनी के सात केस, प्रह्लाद कुमार मोटा पर आर्म्स एक्ट के दो केस तथा सागर उर्फ सूरज पर चोरी, नकबजनी, लूट व आर्म्स एक्ट समेत 45 केस दिल्ली में पहले से दर्ज हैं। पुलिस टीम आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। चोरी की नकदी व संपत्ति की बरामदगी और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

फोन हैक कर लाखों की ठगी, दो खाताधारक गिरफ्तार

फरीदाबाद,एजेंसी। एपीके फाइल भेजकर फोन हैक कर लाखों रुपए की ठगी करने के मामले में साइबर थाना बल्लभगढ़ पुलिस ने दो खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों अमन(21) निवासी उत्तर प्रदेश व दिलखुस बिश्नोई(26) निवासी राजस्थान को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें छह दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि सेक्टर-20बी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 17 मई को उसके टेलीग्राम पर एक लिंक आया जिस पर उसने क्लिक किया तो एक एपीके फाइल उसके फोन में डाउनलोड हो गई और फोन हैक हो गया और अलग-अलग ट्रांजेक्शंस के जरिए उसके खाते से एक लाख एक हजार रुपए कट गये।

ऑटो सवार युवती से मोबाइल छीना

लोनी,एजेंसी। अंकुर विहार थाना क्षेत्र में दिल्ली से घर लौट रही ऑटो सवार युवती के हाथ से बाइक सवार बदमाशों ने आईफोन छीन लिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

अंकुर विहार थाना क्षेत्र की शरद सिटी कॉलोनी में रहने वाली आंचल शर्मा 23 जून शाम को दिल्ली खजूरी से ऑटो में घर लौट रही थी। जब ऑटो विजय विहार अंडरपास के पास पहुंचा तो फोन आ गया। वह फोन पर बात करने लगी। इस दौरान तेज रफ्तार बाइक पर सवार दो बदमाश आए और उनके हाथ से आईफोन छीनकर भाग गए। उन्होंने शोर मचा कर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया।

सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार अमरदीप मौर्या ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

गंग नहर से डूबे युवक का शव बरामद, हत्या की जताई आशंका

दनकौर,एजेंसी।

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के रामपुर जागीर गांव निवासी 26 वर्षीय रविंद्र चेचई उर्फ गोलू का शव सोमवार को दनकौर क्षेत्र के गंग नहर (खेरली नहर) से बरामद हुआ। रविवार दोपहर से लापता युवक की तलाश पुलिस और एनडीआरएफ की टीम कर रही थी। परिजनों ने चार लोगों पर हत्या कर शव नहर में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चौहान ने बताया कि अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है।

रामपुर जागीर निवासी श्रीपाल का इकलौता बेटा रविंद्र चेचई रविवार दोपहर दोस्तों के साथ खेत में गया था। शाम को परिजनों को सूचना मिली कि वह खेरली नहर में डूब गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और देर रात तक नहर में तलाश करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। सोमवार सुबह दोबारा शुरू किए गए सर्च अभियान के दौरान घटना स्थल से करीब 5 किमी दूर चांगोली के पास नहर से रविंद्र का शव बरामद कर लिया गया।

मृतक की पत्नी और तीन बच्चे हैं। मृतक के एक रिश्तेदार का आरोप है कि रविंद्र के हाथ-पैर पर चोट के निशान थे और नाक से खून भी निकल रहा था। ऐसे में आशंका है कि हत्या कर शव नहर में फेंका गया है। दूसरी ओर लोगों में चर्चा है कि मृतक अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया था। नहाते वक्त दोस्तों में तैरकर नहर पार करने की शर्त लगी थी।

सोसाइटी में छज्जे का मलबा गिरने से मासूम घायल

गुरुग्राम, एजेंसी।

गुरुग्राम के सेक्टर-102 स्थित बीपीटीपी एमस्टोरिया सोसाइटी में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। सोसाइटी के ए-ब्लॉक में दूसरी मंजिल के एक फ्लैट के छज्जे का प्लास्टर अचानक गिरने से सात वर्षीय बालक घायल हो गया। घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों में बिल्डर और अनुरक्षण एजेंसी के खिलाफ भारी नाराजगी है। जानकारी के अनुसार, ए-ब्लॉक के भूतल स्थित फ्लैट संख्या ए-31 में रहने वाले विकास चौधरी का सात वर्षीय पुत्र निकुंज सोसाइटी परिसर में खेल रहा था। इसी दौरान दूसरी मंजिल के एक फ्लैट के छज्जे का प्लास्टर अचानक टूटकर नीचे गिर गया। मलबा सीधे बालक के सिर पर आ गिरा, जिससे वह घायल हो गया।

घटना के तुरंत बाद परिजन और अन्य निवासी बालक को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार किया गया। चिकित्सकों के अनुसार, बालक की स्थिति फिलहाल स्थिर और खतरे से बाहर है। घटना के बाद सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर और अनुरक्षण एजेंसी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यह पहली घटना नहीं है। कुछ दिन पहले भी सोसाइटी के डी-ब्लॉक में इसी प्रकार छज्जे का हिस्सा गिरने की घटना सामने आई थी।

बीपीटीपी एमस्टोरिया सोसाइटी के अध्यक्ष रामबीर सिंह ने कहा कि सोसाइटी में आए दिन प्लास्टर और छज्जे गिरने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे निवासियों में किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। उन्होंने बताया कि तीन दिन पहले डी-ब्लॉक में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी और अब ए-ब्लॉक में हादसा सामने आया है।

सोसाइटी की उपाध्यक्ष मोनिका ने आरोप लगाया कि इमारतों के निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर दीवारों और छज्जों में रेत स्पष्ट दिखाई देती है। इस संबंध में कई बार बिल्डर को शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डर अनुरक्षण शुल्क तो वसूल रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बेहद खराब है।

निवासी विनोद सहरावत ने कहा कि सोसाइटी में मलजल शोधन संयंत्र, विद्युत आपूर्ति और साफ-सफाई जैसी अनेक समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं, जिससे लोग परेशान हैं। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। वहीं, निवासियों ने प्रशासन से सोसाइटी की इमारतों की तकनीकी जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।

मकान में चोरी के दौरान फायरिंग करने का आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद, एजेंसी।

मसूरी पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में चोरी के दौरान लोगों को डराने के लिए हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। बरामदगी के आधार पर आरोपी के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा भी बढ़ा दी गई है। पुलिस के अनुसार, थानाक्षेत्र के नाहल गांव में तमकीन भवन का निर्माण करा रहे हैं। 26 जून की देर रात वारिस, सलमान और बिलाल चोरी करने के लिए मकान में घुसे थे।

मकान मालिक और आसपास के लोगों के जाग जाने पर सलमान ने लोगों को डराने के उद्देश्य से तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी और साथियों के साथ फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत के आधार पर हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले में एक आरोपी वारिस को पहले ही गिरफ्तार हो चुका था, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी थी। एसीपी मसूरी अजय सिंह ने बताया कि सोमवार को मुखबिर की सूचना पर फरार आरोपी सलमान निवासी मोहल्ला बिल्लियान ग्राम नाहल को चित्तौड़ पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने करीब दो वर्ष पहले यह तमंचा बहनोई नईम निवासी मंडोली दिल्ली से लिया था। बहनोई की करीब डेढ़ वर्ष पहले मौत हो चुकी है। उसने स्वीकार किया कि चोरी के दौरान लोगों के शोर मचाने पर उन्हें डराने के लिए हवाई फायरिंग की थी, ताकि वह मौके से भाग सके। एसीपी का कहना है कि सलमान का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

सशक्त शिक्षक ही बनाएंगे उज्ज्वल भविष्य: बीके श्वेता

पटौदी,एजेंसी।

ब्रह्माकुमारीज संस्थान के हेलीमंडी स्थित सेवाकेंद्र पर सशक्त शिक्षक, उज्ज्वल भविष्य विषय के तहत शिक्षकों के लिए एक विशेष राजयोग सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में पटौदी, रेवाड़ी सहित गुरुग्राम से लगभग 30 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवाकेंद्र प्रभारी बीके श्वेता ने किया।

उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को राजयोग का गहन अभ्यास कराया। उन्होंने राजयोग के व्यावहारिक लाभ बताते हुए कहा,राजयोग के माध्यम से ही हम स्वयं को आंतरिक रूप से सशक्त कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि सशक्त शिक्षक ही उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

राजयोग से ही नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य जागृत होते हैं। जो आज के समय में शिक्षा जगत के लिए बेहद अनिवार्य हैं। इस मौके पर राजयोग शिक्षिका बीके प्रेम ने मूल्य-आधारित विभिन्न ज्ञानवर्धक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया,एवं कार्यक्रम में मुख्य रूप से वर्तमान समय में तनावमुक्त जीवन शैली अपनाने पर विशेष जोर दिया गया।

इस विशेष अवसर पर संस्थान के नियमित सदस्या व शिक्षिका बीके अनीता एवं पूर्व शिक्षिका बीके ईश्वर रानी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए।

उन्होंने बताया कि राजयोग के नियमित अभ्यास ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इसके प्रभाव से न केवल मानसिक शांति मिली, बल्कि आपसी रिश्तों में भी अभूतपूर्व सुधार आया है।

राष्ट्रीय चैंपियनशिप में फरीदाबाद टीम के साथ आनंद चौधरी, दीपक देशवाल, अभिनंदन एवं श्वेता अनेजा भी उपस्थित रहे

योगासन चैंपियनशिप में मेहर अनेजा ने जीता स्वर्ण व रजत पदक

फरीदाबाद, एजेंसी।

उत्तराखंड के रुडक़ी स्थित सीओईआर यूनिवर्सिटी में 26 से 28 जून तक आयोजित तीसरी राष्ट्रीय योगासन खेल चैंपियनशिप-2026 में फरीदाबाद के खिलाडिय़ों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में सेक्टर-14 स्थित डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल की छात्रा एवं फरीदाबाद की प्रतिभाशाली योगासन खिलाड़ी मेहर अनेजा ने सब जूनियर-बी (बालिका) वर्ग की ट्रेडिशनल योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा आर्टिस्टिक सोलो स्पर्धा में रजत पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया। प्रतियोगिता में मेहर के आयु वर्ग में देशभर से लगभग 200 खिलाडिय़ों ने भाग लिया। कड़े मुकाबले के बीच उन्होंने अपने उत्कृष्ट संतुलन, लचीलेपन, तकनीकी दक्षता एवं आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन के दम पर यह उपलब्धि हासिल की।

मेहर के कोच श्याम कुमार ने बताया कि मेहर पिछले कई वर्षों से पूरे समर्पण एवं अनुशासन के साथ प्रतिदिन लगभग तीन घंटे योगासन का नियमित अभ्यास करती हैं। उनकी कठिन मेहनत, निरंतर अभ्यास और दृढ़ संकल्प का ही परिणाम है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर यह सफलता अर्जित की है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन के आधार पर अब मेहर अनेजा विश्व योगासन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं सुपर सीनियर महिला वर्ग में फरीदाबाद की संगीता शर्मा ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं माधुरी शर्मा, उर्मिल गौतम एवं योगिता ने भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेकर फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व किया और अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में फरीदाबाद टीम के साथ आनंद चौधरी, दीपक देशवाल, अभिनंदन एवं श्वेता अनेजा भी उपस्थित रहे। सभी ने खिलाडिय़ों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतियोगिता के दौरान टीम को आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। इस उपलब्धि पर खिलाडिय़ों, अभिभावकों, प्रशिक्षकों एवं खेल प्रेमियों ने सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि फरीदाबाद के खिलाड़ी आने वाले समय में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिले और देश का नाम और अधिक गौरवान्वित करेंगे।

RNI.No DLHIN/25/A2841
स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मै. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।
संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508
मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com
संपादक देवेंद्र सिंह तोमर
इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

दिल्ली में एक जुलाई से लागू होगी नई ईवी नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी-2026 को मंजूरी दे दी

नई दिल्ली, साहस समाचार।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि प्रदूषण नियंत्रण, आधुनिक परिवहन व्यवस्था और नागरिकों को आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से ईवी नीति तैयार की गयी है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पॉलिसी–2026 को मंजूरी दे दी। यह नीति उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद एक जुलाई से लागू की जायेगी। यह नीति अगले चार वर्ष यानी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने इसे राजधानी के लिए ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया।

उन्होंने कहा कि वर्षों से दिल्ली को ऐसी व्यापक नीति की आवश्यकता थी जो प्रदूषण नियंत्रण, आधुनिक परिवहन व्यवस्था और नागरिकों को आर्थिक लाभ इन तीनों उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर सके। नई ईवी पॉलिसी इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अगले चार वर्षों में इस नीति के तहत 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का प्रत्यक्ष निवेश करेगी।

इसके अतिरिक्त चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट सहित विभिन्न प्रोत्साहनों को जोड़कर नागरिकों को लगभग कुल 15,000 करोड़ रुपये का लाभ दिया जाएगा। देश में पहली बार इतने बड़े निवेश और व्यापक प्रोत्साहनों के साथ किसी राज्य द्वारा ईवी नीति लागू की जा रही है। इस नीति में हाईब्रिड वाहनों को अलग रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी नीति के तहत दोपहिया, तिपहिया, चारपहिया, एन–1 श्रेणी (साढ़े तीन टन तक माल ढोने वाले) के मालवाहक वाहन, एन2 (साढ़े तीन टन से 12 टन माल ढोने वाले) ट्रक और ग्रामीण सेवा वाहनों को शामिल किया गया है।

सरकार ने किसी भी श्रेणी में प्रोत्साहन की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। जितने अधिक नागरिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे, सरकार उतने ही अधिक लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति लागू होने के पहले वर्ष इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30,000 रुपये तक, दूसरे वर्ष 20,000 रुपये तक और तीसरे वर्ष 10,000 रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जायेगा।

इसी तरह इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन खरीदने पर पहले वर्ष 50,000 रुपये तक, दूसरे वर्ष 30,000 रुपये तक और तीसरे वर्ष 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जायेगा। वहीं, एन–1 श्रेणी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने पर एक लाख रुपये तक का खरीद प्रोत्साहन दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए सरकार ने आकर्षक स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी प्रदान किया है। इसके अंतर्गत बीएस–4 या उससे पुराने दोपहिया वाहन स्क्रैप करने पर 10,000 रुपये, तिपहिया पर 25,000 रुपये, चारपहिया वाहन पर एक लाख रुपये, एन–1 ट्रक पर 50,000 रुपये और ग्रामीण सेवा वाहन पर 15,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

इसके साथ ही सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। चार पहिया वाहनों के लिए यह छूट 30 लाख रुपये तक की एक्स–शोरूम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर ही लागू होगी। सभी प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जायेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के कारण है।

इसी कारण नीति में इन श्रेणियों को विशेष प्राथमिकता दी गयी है ताकि प्रदूषण में प्रभावी कमी लायी जा सके। भारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए अधिसूचना जारी होने के तीन माह के भीतर खरीदे गए पहले 1,000 एन2 इलेक्ट्रिक ट्रकों को 10 वर्षों तक 'नो–एंट्री' समय से छूट दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क इस नीति की सफलता का आधार होगा।

इसी उद्देश्य से नीति अवधि के दौरान दिल्ली में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने इस नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद, पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, संबंधित विभागों के अधिकारियों और सभी हितधारकों का आभार व्यक्त किया।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

हर हार की शुरुआत गलत कप्तान से ही होती है

नई दिल्ली। क्रिकेट के मैदान में जब कोई टीम लगातार हारती है तो सबसे पहले उंगली कप्तान पर उठती है। टीवी स्टूडियो से लेकर चाय की दुकान तक बहस छिड़ जाती है कि कप्तान बदलो, टीम बदल जाएगी। कुछ हद तक यह बात सही भी है, क्योंकि कप्तान सिर्फ टॉस करने वाला खिलाड़ी नहीं होता, वह पूरी टीम की सोच, रणनीति और दिशा तय करता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कप्तान कैसा निकला। असली सवाल यह है कि कप्तान चुना कैसे गया?

यहीं से राजनीति और क्रिकेट एक–दूसरे के सामने आईना बनकर खड़े हो जाते हैं।

क्रिकेट में अगर किसी खिलाड़ी को उसकी प्रतिभा के बजाय लॉबी, रिश्ते या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की पसंद के कारण कप्तानी मिल जाए तो नुकसान एक टूर्नामेंट तक सीमित रह सकता है। लेकिन लोकतंत्र में अगर देश की बागडोर ऐसे हाथों में चली जाए जो नेतृत्व की योग्यता से अधिक प्रचार, प्रबंधन या व्यक्तिपूजा के कारण ऊपर पहुंचे हों, तो उसकी कीमत सिर्फ एक सरकार नहीं, पूरी पीढ़ी चुकाती है।

हार कभी अचानक नहीं आती। हार का पहला दिन वह नहीं होता जब स्कोरबोर्ड पर पराजय दर्ज होती है। हार का पहला दिन वह होता है, जब चयन की मेज़ पर योग्यता हार जाती है और चापलूसी जीत जाती है। जब अनुभव को किनारे कर सुविधा को आगे कर दिया जाता है। जब सच बोलने वालों की जगह सिर हिलाने वालों को महत्व मिलने लगता है। मैदान में दिखाई देने वाली हार तो सिर्फ उस फैसले का सार्वजनिक ऐलान होती है, जिसकी पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है।

किसी भी टीम का कप्तान अपने अकेले के दम पर मैच नहीं जिताता। लेकिन वह अपने अकेले के दम पर पूरी टीम को हरवा जरूर सकता है। क्योंकि कप्तान का सबसे बड़ा काम रन बनाना नहीं, सही आदमी पर भरोसा करना होता है। किसे मौका मिलेगा, किसे बाहर बैठाया जाएगा, किस पर कठिन समय में विश्वास किया जाएगा1 यही फैसले जीत और हार का अंतर तय करते हैं। जब ये फैसले योग्यता से नहीं, निष्ठा से होने लगें, तब समझ लेना चाहिए कि हार ने ड्रेसिंग रूम में प्रवेश कर लिया है। यही नियम राजनीति पर भी लागू होता है। एक गलत नेता सिर्फ गलत भाषण नहीं देता, वह गलत लोगों को जिम्मेदारी देता है। गलत सलाहकार चुनता है। योग्य लोगों से डरता है। स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर करता है। अपने आसपास ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी करता है जो सच नहीं, सिर्फ वही कहते हैं जो वह सुनना चाहता है। धीरे–धीरे पूरी व्यवस्था उसकी सोच का प्रतिबिंब बन जाती है। तब देश की हार किसी युद्ध में नहीं होती, बल्कि फैसलों में होने लगती है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा, न्याय, प्रशासन और लोकतंत्र1 सब पर उसका असर दिखाई देने लगता है।

किसी भी राष्ट्र का पतन एक दिन में नहीं होता। वह गलत फैसलों की लंबी श्रृंखला का परिणाम होता है। और लगभग हर श्रृंखला की पहली कड़ी होती है, गलत आदमी के हाथ में कमान। देश हो या क्रिकेट, हार की शुरुआत गलत कप्तान से होती है1

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां हार भी अक्सर जीत की तरह पेश की जाती है। प्रचार इतना ताकतवर हो चुका है कि असफलता को उपलब्धि और चुप्पी को सहमति साबित करने की कला विकसित हो गई है। जनता को बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है, जबकि हकीकत धीरे–धीरे उसकी जेब, उसकी नौकरी, उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य में दिखाई देने लगती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

क्रिकेट में एक गलत कप्तान का असर तुरंत दिखाई देता है। ड्रेसिंग रूम दो हिस्सों में बंटने लगता है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी हताश होने लगते हैं। फैसलों पर भरोसा खत्म होने लगता है। खिलाड़ी विरोधी टीम से कम, अपने ही नेतृत्व से ज्यादा लड़ने लगते हैं। अंततः हार स्कोरबोर्ड पर दर्ज हो जाती है। राजनीति में यह प्रक्रिया कहीं अधिक खतरनाक होती है। यहां स्कोरबोर्ड नहीं होता, इसलिए हार देर से दिखाई देती है। कभी वह बेरोजगारी के आंकड़ों में छिपी होती है, कभी किसानों की बदहाली में, कभी न्याय मिलने में हो रही देरी में, कभी शिक्षा और स्वास्थ्य की गिरती गुणवत्ता में और कभी समाज में बढ़ती नफरत के रूप में। लेकिन समर्थकों की आंखों पर प्रचार का ऐसा पर्दा डाल दिया जाता है कि उन्हें हर सवाल साजिश और हर आलोचना देशद्रोह लगने लगती है।

यहीं सबसे बड़ी त्रासदी शुरू होती है।

जब कप्तान गलत हो तो टीम उसे बदल सकती है। लेकिन जब पूरी व्यवस्था ही गलत कप्तान को बचाने में लग जाए, तब हार स्थायी होने लगती है। फिर चयन योग्यता से नहीं, वफादारी से होने लगता है। संस्थाएं अपने कर्तव्य से ज्यादा सत्ता की सुविधा देखने लगती हैं। सच बोलने वालों को किनारे कर दिया जाता है और झूठ बोलने वालों को पुरस्कार मिलने लगते हैं। धीरे–धीरे पूरी व्यवस्था एक ऐसे प्रतिध्वनि कक्ष में बदल जाती है, जहां सिर्फ कप्तान की आवाज सुनाई देती है।

इतिहास उठाकर देख लीजिए। किसी भी देश का पतन इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास संसाधन कम थे। अधिकांश देशों का नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि गलत लोग सही जगहों पर बैठ गए थे। उन्हें चुनौती देने वाले चुप करा दिए गए थे और ताली बजाने वालों को निर्णय लेने का अधिकार मिल गया था।

क्रिकेट में एक खराब कप्तान के कारण विश्व कप हाथ से निकल सकता है। लेकिन देश में गलत नेतृत्व के कारण पूरी पीढ़ी अवसरों से वंचित हो सकती है। एक मैच हारने के बाद अगला मैच खेला जा सकता है। लेकिन अगर शिक्षा की दिशा गलत तय कर दी जाए, न्याय व्यवस्था कमजोर कर दी जाए, संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाए और समाज को स्थायी विभाजन की ओर धकेल दिया जाए, तो उसकी भरपाई दशकों में भी नहीं होती।

आईआईआईटी दिल्ली को मिली ईयू-इंडिया स्टूडेंट एंबेसडर नेटवर्क में जगह

नई दिल्ली,साहस समाचार।

इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) दिल्ली को बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। संस्थान का चयन यूरोपीय संघ (ईयू) इंडिया स्टूडेंट एंबेसडर नेटवर्क के लिए देश के 20 चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों में किया गया है।

यह पहल भारत में यूरोपीय संघ के पब्लिक एंड कल्चरल डिप्लोमेसी प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

संस्थान के फैकल्टी सदस्य डॉ. जैनेंद्र शुक्ला ने कहा कि यह चयन आईआईआईटी–दिल्ली की वैश्विक पहचान का प्रमाण है। इससे छात्रों को अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों से जुड़ने, छात्र विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने और भारत–यूरोप शैक्षणिक साझेदारी को मजबूत करने के अवसर मिलेंगे।

ईयू–इंडिया स्टूडेंट एंबेसडर के लिए चयनित पीएचडी शोधार्थी जोशिता यादव ने कहा कि यह मंच विभिन्न देशों के छात्रों और विशेषज्ञों के साथ संवाद तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान का अवसर प्रदान करेगा। छात्र एंबेसडर हार्दिक मदान के अनुसार, इस पहल से भारतीय छात्रों को अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी और उनमें भागीदारी का अवसर मिलेगा। संस्थान ने कहा कि यह नेटवर्क छात्र गतिशीलता, कौशल विकास और वैश्विक शैक्षणिक साझेदारियों को नई मजबूती देगा।

जामिया में कई कोर्स में दाखिला शुरू

नई दिल्ली,साहस समाचार। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के स्नातक दाखिलों के लिए 25 पाठ्यक्रमों में प्रवेश कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी–यूजी) 2026 के स्कोर के आधार पर दाखिला दे रहा है। वहीं, अन्य कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित कर चुका है और परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां स्नातक सहित अन्य विषयों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विश्वविद्यालय के अनुसार, इस वर्ष स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

प्रवेश परीक्षाएं देश के 16 शहरों में आयोजित की गईं। बीटेक में प्रवेश जेईई (मेन) 2026, बीआर्क में नाटा 2026 तथा इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (आईटीईपी बीएड) में प्रवेश एनसीईटी 2026 की मेरिट के आधार पर हो रहा है।

पुलिस ने दो वांछित अपराधियों को दबोचा, मुठभेड़ में एक घायल

नई दिल्ली, साहस समाचार।

राष्ट्रीय राजधानी की नजफगढ़ थाना पुलिस ने द्वारका जिले में एक अभियान चलाकर दो वांछित अपराधियों रोहित लांबा उर्फ अमित उर्फ मोहित और रितिक ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि छिपाकर रखे गए हथियार को ले जाने के दौरान हुई कथित मुठभेड़ में रोहित लांबा के पैर में गोली लगी है। उसके पास से एक अवैध पिस्तौल, एक मैगजीन, चार जिंदा कारतूस और तीन खाली कारतूस बरामद किए गए हैं। द्वारका के पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने कहा कि यह कार्रवाई जिले के 'नो गन्स, नो गैंग्स' अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य अवैध हथियारों और संगठित आपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसना है।

सिंह ने कहा कि पुलिस टीमों को गैंग के सदस्यों, आदतन अपराधियों और अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी रखने और लक्षित कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिये गये हैं। पुलिस के अनुसार, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नजफगढ़ थाने की टीम ने 28 जून को शक्ति नगर एक्सटेंशन में साईं बाबा मंदिर के पास एक स्थान पर छापेमारी की और रोहित लांबा तथा रितिक ठाकुर को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान रोहित लांबा ने कथित तौर पर उस जगह का खुलासा किया जहां उसने अवैध पिस्तौल छिपाई थी।

पुलिस ने बताया कि जब हथियार की बरामदगी के लिए उसे मौके पर ले जाया जा रहा था, तब रोहित लांबा ने झाड़ियों से हथियार निकालकर पुलिस टीम पर गोली चला दी। अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिससे उसके पैर में चोट आई और फिर उसे निहत्था कर हिरासत में ले लिया गया।

दिल्ली में आज होगा एसआईआर

नई दिल्ली,साहस समाचार। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान 30 जून से शुरू होगा और 29 जुलाई तक बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर–घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र एकत्र करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोमवार को बताया कि राजधानी में एसआईआर 2026 अभियान की तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग ने 14 मई को इस अभियान की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ स्तर अधिकारी घर–घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र एकत्र करेंगे। इसके बाद पांच अगस्त को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होगा, जबकि दावे और आपत्तियां पाँच अगस्त से चार सितंबर तक दर्ज करायी जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची सात अक्टूबर को प्रकाशित की जायेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार दिल्ली में वर्तमान में कुल 1,45,10,298 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 77.11 लाख पुरुष, 67.98 लाख महिला और 1,024 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। राजधानी में 13,033 मतदान केंद्र स्थापित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मतदाता बनने के लिए भारतीय नागरिक होना, निर्धारित तिथि पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यदि किसी घर पर बीएलओ के पहुंचने के समय ताला लगा मिलेगा तो गणना प्रपत्र वहां छोड़ दिया जायेगा और उसे प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन बार पुनः दौरा किया जायेगा। मतदाताओं को केवल गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा करना होगा तथा किसी भी प्रकार का दस्तावेज संलग्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। सहायता के लिए निर्वाचन आयोग का हेल्पलाइन नंबर 1950, जिला मुख्यालयों एवं मतदाता केंद्रों पर हेल्पडेस्क तथा ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

वायलेट लाइन पर व्यस्त समय में मेट्रो सेवा प्रभावित रही

नई दिल्ली, साहस समाचार।

वायलेट लाइन पर सिग्नल में खराबी के कारण सोमवार सुबह मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहा। इससे व्यस्त समय में यात्रियों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने से केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस, कश्मीरी गेट सहित वायलेट लाइन के कई स्टेशनों के प्लेटफार्म पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सुबह 9:17 बजे एक्स पर पोस्ट कर वायलेट लाइन के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर सिग्नल में खराबी होने की सूचना दी।

इसके कुछ ही मिनटों में बाद परिचालन सामान्य होने की बात कही। हालांकि, कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर करीब आधे घंटे तक परिचालन ठप रहने की बात कही। एक्स पर राहुल नामक एक व्यक्ति ने लिखा कि ट्रेन सुबह 9:05 बजे सराय स्टेशन पहुंची और 9:33 बजे चलना शुरू की। परी नामक एक महिला यात्री ने लिखा कि सुबह 8:45 बजे से ही मेट्रो खान मार्केट से केंद्रीय सचिवालय के बीच ट्रेन रुकी रही।

वहीं, राहुल जैन ने मेट्रो के आधे घंटे से रुके होने की बात कही। पिछले कुछ दिनों में सिग्नल में खराबी के कारण मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने की यह तीसरी घटना है।

इससे पहले 26 जून को सिग्नल में खराबी के कारण ग्रीन लाइन पर और 24 जून को ब्लू लाइन पर मेट्रो का परिचालन प्रभावित हुआ था।

8 देशों के विदेशी राजदूत व धार्मिक विद्वान लद्दाख में सम्मिलित हुए

नई दिल्ली,साहस समाचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी के नेतृत्व में 23 से 27 जून 2026 तक, 5 दिवसीय 30वें सिंधु दर्शन यात्रा कुंभ का सफल आयोजन किया गया। इसका शुभारम्भ माननीय उपराज्यपाल लेह लद्दाख विनय कुमार सक्सेना ने किया। उपस्थित 3,000 श्रद्धालुओं ने पारंपरिक नृत्य, भक्ति गीत व संगीत की धूनों पर राष्ट्रीय ध्वज लहराते हुए भाग लिया। दूसरे दिन हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल कविन्दर गुप्ता ने भी भाग लिया। स्वागत भाषण लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद् पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने दिया।

भारत सरकार सांस्कृतिक मंत्रालय की टीम ने देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला भव्य गीत, संगीत व नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया। सिंधू दर्शन यात्रा समिति महासचिव भूपेंद्र कंसल व टीम ने कार्यक्रम का सफलता पूर्वक समन्वय किया। इसमें सिंधू दर्शन यात्रा समिति अध्यक्ष मुरलीधर मखीजा और हिमालय परिवार राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष परमजीत सिंह गिल भी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में महिलाओं नेत्रियों ने कलश पूजन भी किया। 8 देशों के विदेशी राजदूतों की सहभागिता, 30वें सिंधु दर्शन यात्रा कुंभ की विशेषता रही। यह इस कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को रेखांकित करती है। उच्चायुक्तों में जगन्नाथ सामी (फिजी), श्रीमती शीलाबाई बापू (मॉरिशस), सुश्री महिषिनी कोलोन (श्रीलंका), प्रो. अनिल सूकलाल (दक्षिण अफ्रीका), चंद्रदथ सिंह (त्रिनिदाद और टोबैगो) तथा राजदूत फर्नांडो बुचेली वर्गास (इक्वाडोर), जुआज रोलैंडो अंगुलो मोनसाल्वे (चिली) और केविन केली (आयरलैंड) आदि धर्मपत्नी संग शामिल हुए।

'टेक4फ्यूचर' कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का सशक्त उदाहरण है

सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगा अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण

नई दिल्ली, साहस समाचार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अनुरूप सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिकी एवं अत्याधुनिक तकनीकों से जोड़ने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। दिल्ली के शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को आयोजित 'टेक4फ्यूचर – फ्यूचर मेकर्स इनोवेटर्स बूटकैंप' के भव्य समापन एवं नवाचार प्रदर्शनी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम दिल्ली सरकार के सीएम श्री विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए आयोजित तीन सप्ताह के गहन कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिकी अभियांत्रिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन का प्रतीक रहा।

इस अवसर पर शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के चार प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों—दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय महिला तथा इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली—के साथ तीन वर्षों के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। जून 2026 से प्रभावी इन समझौतों के अंतर्गत संबंधित संस्थानों के प्राध्यापक एवं शोधार्थी सीएम श्री विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को पूर्णतः निःशुल्क शैक्षणिक मार्गदर्शन, पाठ्यक्रम समृद्धि तथा अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं तक पहुंच उपलब्ध कराएंगे।

इस अवसर पर आशीष सूद ने कहा कि 'टेक4फ्यूचर' कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का सशक्त उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह पहल सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिकी और उन्नत अभियांत्रिकी जैसी आधुनिक तकनीकों से सीधे जोड़ रही है, जिससे विद्यार्थियों की सामाजिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा और नवाचार क्षमता उनके भविष्य का निर्धारण करेगी। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी केवल रोबोटिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वित्त, मानविकी, माध्यम अध्ययन तथा विधि अध्ययन जैसे विषयों में भी विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेगी। साथ ही विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं, त्रिआयामी मुद्रण सुविधाओं तथा नवप्रवर्तन संवर्धन केंद्रों तक प्रत्यक्ष पहुंच भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कार्यक्रम के अंतर्गत सीएम श्री विद्यालयों के 100 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन उनकी योग्यता, विश्लेषणात्मक क्षमता और वैज्ञानिक अभिरुचि के आधार पर बहु–स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। चयनित विद्यार्थियों को 20 अंतर्विषयी दलों में विभाजित कर 140 घंटे से अधिक का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने अत्याधुनिक त्रिआयामी मुद्रण प्रयोगशाला, उन्नत निर्माण प्रयोगशाला तथा नवाचार केंद्र जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हुए समस्या की पहचान से लेकर समाधान की परिकल्पना, प्रारूप निर्माण, परीक्षण तथा प्रस्तुतीकरण तक नवाचार की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।

कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों की 20 टीमों ने 20 पूर्णतः कार्यशील तकनीकी प्रारूप प्रस्तुत किए। ये प्रारूप स्मार्ट शहर, कृषि, आपदा प्रबंधन, सहायक प्रौद्योगिकी तथा औद्योगिक नवाचार जैसी वास्तविक चुनौतियों के समाधान पर आधारित थे। आशीष सूद ने कहा कि यह पहल 'विकसित भारत–2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवाचार आधारित, तकनीकी रूप से दक्ष और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

संपादकीय

लोकतंत्र में सवाल पूछना भी देशभक्ति है

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी सबसे बड़ी ताकत केवल चुनाव नहीं, बल्कि वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकती है, मीडिया सरकार के कामकाज की समीक्षा कर सकता है और संस्थाएं निष्पक्ष होकर जवाबदेही तय कर सकती हैं। जब सवाल पूछने वालों को विरोधी या दुश्मन मान लिया जाता है, तब लोकतंत्र की आत्मा कमजोर होने लगती है। आज देश तेज़ी से विकास के अनेक दावे कर रहा है। एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे का आधुनिकीकरण हो रहा है, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है और भारत वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह सकारात्मक परिवर्तन हैं और इनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन विकास की वास्तविक कसौटी केवल उपलब्धियों का प्रचार नहीं, बल्कि उन समस्याओं का समाधान भी है जिनका सामना आम नागरिक प्रतिदिन करता है।

नगर निगम हो, नगर परिषद हो या कोई अन्य सरकारी विभाग—यदि कहीं भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनियमितता की शिकायत सामने आती है, तो उस पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। जनता कर इसलिए नहीं देती कि उसका पैसा फाइलों में गुम हो जाए या योजनाएं केवल कागज़ों तक सीमित रह जाएं। जनता यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक रुपये का ईमानदारी से उपयोग हो और हर अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा से करे।

मीडिया की भूमिका भी इसी जवाबदेही को मजबूत करने की है। एक जिम्मेदार समाचार पत्र या पत्रकार का उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था को बदनाम करना नहीं, बल्कि तथ्यों के आधार पर उन मुद्दों को सामने लाना है जो जनहित से जुड़े हों। यदि किसी रिपोर्ट में उठाए गए सवालों का जवाब दस्तावेज़ों और तथ्यों के साथ दिया जाता है, तो इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है। लेकिन यदि सवालों से बचने या उन्हें दबाने का प्रयास किया जाता है, तो जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है।

आज सोशल मीडिया के दौर में सूचना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक तेज़ हो गया है। हर व्यक्ति कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। यह अवसर भी है और चुनौती भी। झूठी खबरें, अधूरी जानकारी और अफवाहें समाज में भ्रम पैदा कर सकती हैं। इसलिए पत्रकारिता की जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। सत्यापन, निष्पक्षता और तथ्यों की पुष्टि के बिना प्रकाशित या प्रसारित कोई भी सूचना समाज को नुकसान पहुंचा सकती है।

सरकारों को भी यह समझना होगा कि आलोचना हमेशा विरोध नहीं होती। कई बार जनता और मीडिया द्वारा उठाए गए प्रश्न ही सुधार का रास्ता दिखाते हैं। इतिहास गवाह है कि अनेक बड़ी प्रशासनिक और नीतिगत कमियों का पता जनसरोकार वाली पत्रकारिता और नागरिकों की जागरूकता से ही चला। इसलिए आलोचना को लोकतंत्र का आवश्यक हिस्सा मानकर उसका सकारात्मक उत्तर देना अधिक उचित है।

दूसरी ओर, नागरिकों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। केवल शिकायत करना पर्याप्त नहीं है। कानून का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, करों का ईमानदारी से भुगतान करना और मतदान के साथ-साथ जनहित के मुद्दों पर जागरूक रहना भी लोकतांत्रिक कर्तव्य हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी समान रूप से पालन किया जाएगा। आज आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है जिसमें पारदर्शिता केवल नारे तक सीमित न रहे। सरकारी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण, समयबद्ध शिकायत निवारण, डिजिटल पारदर्शिता, स्वतंत्र जांच और सूचना के अधिकार जैसे साधनों को और प्रभावी बनाना होगा। जब निर्णय प्रक्रिया खुली होगी और जवाबदेही तय होगी, तब भ्रष्टाचार के अवसर स्वतः कम होंगे तथा जनता का भरोसा भी बढ़ेगा।

भारत आज अमृतकाल की बात कर रहा है। यह लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति से हासिल नहीं होगा, बल्कि सुशासन, ईमानदार प्रशासन, स्वतंत्र मीडिया और जागरूक नागरिकों के संयुक्त प्रयास से ही संभव होगा। लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता में बैठे लोगों की प्रशंसा से नहीं, बल्कि उन प्रश्नों से बढ़ती है जो जनहित में पूछे जाते हैं और जिनका उत्तर जिम्मेदारी से दिया जाता है।

एनडीए कुनबे में सांसद बढ़े पर बढ़ गया अंदरूनी असंतोष

दिलीप कुमार पाठक

भारतीय राजनीति में इस समय एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। विपक्ष के सांसदों की टूट-फूट से सत्ताधारी एनडीए का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि सरकार पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित हो चुकी है। लेकिन जब हम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों और संसद के आंकड़ों की गहराई में जाते हैं, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है।

भारतीय राजनीति में इस समय एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिल रहा है। विपक्ष के सांसदों की टूट-फूट से सत्ताधारी एनडीए का कुनबा लगातार बड़ा हो रहा है। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि सरकार पहले से कहीं अधिक मजबूत और सुरक्षित हो चुकी है। लेकिन जब हम दिल्ली के राजनीतिक गलियारों और संसद के आंकड़ों की गहराई में जाते हैं, तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। बाहर से ताकतवर दिख रही इस सरकार के भीतर तनाव की एक नई लहर दौड़ गई है।

साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने दम पर बहुमत का जाजुई आंकड़ा नहीं छू सकी थी। तब एनडीए ने 293 सीटों के साथ सरकार का गठन किया था। सरकार को टिकाए रखने के लिए 272 सांसदों की जरूरत होती है। हाल के दिनों में विपक्षी खेमे, खासकर टीएमसी और शिवसेना, जैसे दलों से सांसदों के पाला बदलने के कारण अब एनडीए का आंकड़ा 313 के पार पहुंच चुका है। सीधे गणित से देखें तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इस सरकार को गिराना विपक्ष के लिए पूरी तरह असंभव है। सरकार गिरने का कोई तात्कालिक खतरा नहीं है, इसलिए सरकार के पूरी तरह अस्थिर होने का दावा तकनीकी रूप से गलत साबित होता है। लेकिन असली पेंच सरकार के बने रहने का नहीं, बल्कि उसके कामकाज और आंतरिक तालमेल का है।

सरकार का कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के भीतर तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। इस समय सबसे बड़ी अटकलें मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल को लेकर लगाई जा रही हैं। बाहर से आए दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें सरकार में जगह देनी होगी। इसकी वजह से मौजूदा कई मंत्रियों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि नए चेहरों को एडजस्ट करने के लिए कई पुराने और कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है या उनसे भारी-भरकम मंत्रालय छीने जा सकते हैं। इस संभावित फेरबदल की वजह से मंत्रियों और मूल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की आग सुलगने लगी है। पुराने नेताओं को लगने लगा है कि बरसों तक पार्टी के लिए खून-पसीना बहाने के बाद भी, ऐन मौके पर दलबदलुओं को तवज्जो दी जा रही है। तनाव का दूसरा बड़ा कारण गठबंधन की छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों में देखा जा रहा है।

नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे दल अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर गहरे संकट और चिंता में हैं। दरअसल, जब एनडीए के पास 293 सीटें थीं, तब इन छोटे दलों की बैसाखियों के बिना सरकार एक कदम भी नहीं चल सकती थी। लेकिन अब विपक्ष से आए सांसदों के कारण सरकार का अपना आंकड़ा 313 पार कर गया है। इस नए समीकरण ने छोटे दलों की सौदेबाजी की ताकत को लगभग खत्म कर दिया है। उन्हें डर है कि भाजपा अब उनके क्षेत्रीय हितों को नजरअंदाज कर सकती है, जिससे उनके राज्यों में उनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा।इस राजनीतिक उठापटक के बीच, हालिया विवादों ने सरकार की सुशासन की छवि पर भी दबाव बना दिया है। अयोध्या में

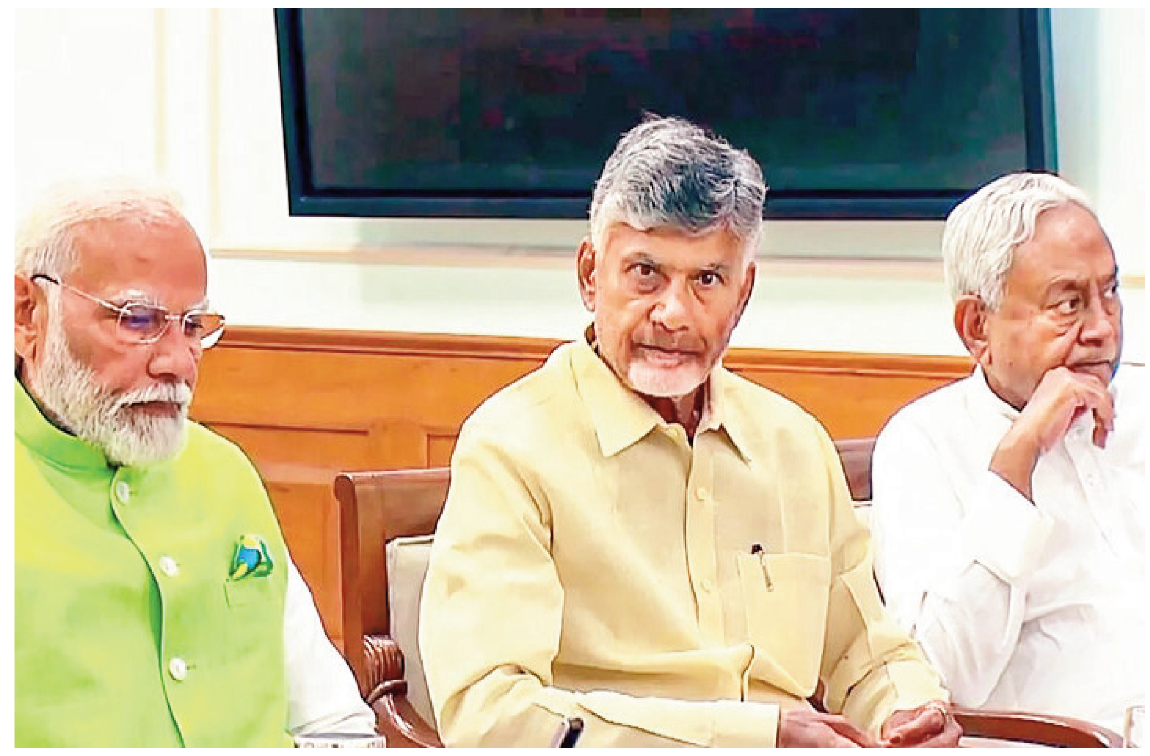

सरकार का कुनबा तो बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही गठबंधन के भीतर तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। इस समय सबसे बड़ी अटकलें मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल को लेकर लगाई जा रही हैं। बाहर से आए दिग्गज नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उन्हें सरकार में जगह देनी होगी। इसकी वजह से मौजूदा कई मंत्रियों पर भारी दबाव देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि नए चेहरों को एडजस्ट करने के लिए कई पुराने और कद्दावर मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है या उनसे भारी-भरकम मंत्रालय छीने जा सकते हैं। इस संभावित फेरबदल की वजह से मंत्रियों और मूल पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की आग सुलगने लगी है। पुराने नेताओं को लगने लगा है कि बरसों तक पार्टी के लिए खून-पसीना बहाने के बाद भी, ऐन मौके पर दलबदलुओं को तवज्जो दी जा रही है। तनाव का दूसरा बड़ा कारण गठबंधन की छोटी और क्षेत्रीय पार्टियों में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे दल अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर गहरे संकट और चिंता में हैं।

राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का बड़ा मामला सामने आने से जहां एक तरफ धार्मिक और राजनीतिक बहस छिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से जुड़ा भूमि आवंटन का ताजा प्रकरण भी विपक्ष के हाथों में बड़ा मुद्दा बन गया है। इन दोनों ही गंभीर मामलों ने भाजपा को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है, जिससे संगठन के भीतर का आपसी तनाव और अधिक गहरा गया है। इस पूरे दलबदल के पीछे सरकार की अपनी एक बड़ी रणनीति भी छिपी है। सरकार संसद में मनमाने और कड़े बिल पारित कराना चाहती है।

भाजपा का मुख्य एजेंडा सिर्फ सरकार चलाना नहीं, बल्कि परिसीमन और 'एक देश, एक चुनाव' जैसे बड़े संवैधानिक सुधारों को लागू करना है। इन ऐतिहासिक बदलावों के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत यानी 362 सीटों की जरूरत होती है। सरकार इसी जादुई आंकड़े को छूने के लिए विपक्ष में तोड़फोड़ कर रही है।

हालांकि, इतने सांसदों को जोड़ने के बाद भी सरकार अभी दो-तिहाई के आंकड़े से दूर है, जिससे विधायी स्तर पर उसकी राह अब भी आसान नहीं दिखती। कुल मिलाकर देखें तो यह दावा पूरी तरह सही है कि सांसदों के आने से एनडीए का संख्या बल तो बढ़ा है, लेकिन सरकार के भीतर आंतरिक तनाव और असंतोष अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। सरकार की उम्र भले ही लंबी हो गई हो, लेकिन मंत्रियों की कुर्सी छिनने का डर, पुराने नेताओं की नाराजगी, क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का संकट और हालिया भ्रष्टाचार के आरोप इस सरकार की राजनीतिक स्थिरता को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं।

ईरान कैसे बना महाशक्ति

तनवीर जाफ़री

अमेरिका, इज़राइल द्वारा ईरान पर जून 2025 में 12 दिन का और उसके बाद 28 फरवरी 2026 को लगभग 40 दिन का युद्ध थोपा गया था। अचानक थोपे गये इस युद्ध में हालांकि ईरान को जान व माल का काफ़ी नुक़सान हुआ परन्तु ईरान ने भी परमाणु शक्ति संपन्न हुये बिना ही इन दोनों परमाणु शस्त्र संपन्न देशों को ऐसा करारा जवाब दिया कि आख़िरकार स्वयं को विश्वविजेता कहलाने वाले अमेरिका को युद्ध से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने पड़े। इतने कम समय के युद्ध में अमेरिका व इस्राईल को इतना नुक़्सान पहले कभी नहीं उठाना पड़ा। आज अमेरिका से लेकर इस्राईल तक की जनता यह स्वीकार कर रही है कि इस युद्ध में हर मोर्चे पर ईरान ही विजेता रहा है । क्योंकि ईरान अमेरिका द्वारा युद्धोपरांत हस्ताक्षर किये गये सहमति पत्र में स्वीकार की गयी अधिकांश बातें ईरान के हक़ में तथा ईरान को फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। हालांकि अमेरिका द्वारा पुनः युद्धविराम के समझौते का उल्लंघन कर ईरान पर कई बड़े हमले करने व ईरान द्वारा भी कुवैत व बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कड़ी जवाबी कार्रवाई करने के समाचार हैं। ऐसे में सवाल यह है कि लगभग 50 वर्षों से वैश्विक प्रतिबंधों का भी सामना करने वाले इस देश ने अत्यंत सीमित संसाधनों के बावजूद अमेरिका व इज़राइल जैसे शक्तिशाली,चालबाज़ व छल कपट में माहिर देशों का एक साथ मुक़ाबला कैसे किया ?

इसमें कोई संदेह नहीं कि ईरानी लोग मुसलमानों के उस शिया वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं जो हज़रत अली,हज़रत इमाम हुसैन व करबला की उस घटना से प्रेरणा लेते हैं जो असत्य,अन्याय व अत्याचार के आगे कभी सर न झुकाने की सीख देती है। इसके साथ साथ ईरान ने धरातल पर जो दूरगामी व सधी हुई रणनीति अपनाई उसी ने ईरान को न केवल अमेरिका व इस्राईल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों पर विजय दिलाई बल्कि ईरान को विश्व की महाशक्तियों की सूची में भी शामिल कर दिया। अमेरिका व इस्राईल की नाराज़गी के भय से पूरे युद्ध के दौरान आधिकारिक रूप से किसी भी देश ने ईरान की सहायता नहीं की न ही ईरान ने खाने-पीने की चीज़ों व दवाईयों तक के लिये कोई अपील जारी की। युद्ध शुरू होते ही रोटी, पेट्रोल और डीज़ल ईरानियों के लिये निःशुल्क कर दिए गए ताकि उन्हें युद्ध के बोझ का एहसास न हो। अमेरिकी व इस्राईली भीषण बमबारी के बावजूद, एक भी ईरानी नागरिक ने पलायन नहीं किया हाँ विदेशों में रहने वाले हज़ारों ईरानी अपने देश की रक्षा की ग़रज़ से स्वदेश वापस ज़रूर लौटे। युद्ध के दौरान, कई प्रमुख मंत्री अमेरिका विरोधी प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों के साथ निडर होकर सारी सारी रात सड़कों पर नज़र आये। हद तो यह है कि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकीयान स्वयं बाज़ारों में जाकर वस्तुओं के मूल्य व जनसुविधाओं का जायज़ा लेते नज़र आये ।

सवाल यह है कि ईरान के लोगों व वहाँ के नेतृत्व में इतना दृढ़ विश्वास आया कहाँ से ? तो आइये नज़र डालते हैं कुछ उन छोटी छोटी सामान्य बातों पर जिसे भले ही दुनिया के अधिकांश देशों के लोग व वहाँ का नेतृत्व सम्मान या सम्पन्नता की नज़रों से क्यों नदेखते हों परन्तु ईरान के लोगों ने इनसे दूर रहना ही राष्ट्रहित में समझा। मिसाल के तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपना निजी मकान तक नहीं ख़रीदा। ईरान के मंत्रियों और शीर्ष सैन्य अधिकारीयों व अन्य आला अफ़सरों के बच्चे विदेश में पढ़ाई करने नहीं जाते। ईरानी सरकार का कोई भी सदस्य और प्रशासनिक अधिकारी विदेशी बैंकों में पैसे जमा नहीं कर सकते। ईरान का कोई भी मंत्री,जनरल या उच्चाधिकारी देश के बाहर कोई दूसरा मकान नहीं बनाता। ईरान के सुप्रीम लीडर बिना दिखावे व प्रचार के रोज़ाना 18 घंटे काम करते हैं। वहां कोई भी अमेरिकन या यूरोपीय शिक्षण संस्थान नहीं हैं। ईरान में साक्षरता दर 97 प्रतिशत है क्योंकि शिक्षा मुफ़्त है। इसीलिये वहां के अधिकांश लोग डॉक्टर इंजीनियर,प्रोफ़ेसर आदि हैं जिसका साक्षात नतीजा ईरान ने पिछले युद्ध के दौरान अपनी ड्रोन व मिसाईल क्षमता को साबित कर दुनिया को दिखा भी दिया।

तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वहां जनता की जेब काटने जैसी कोई टैक्स व्यवस्था नहीं है। यदि परिस्थितिवश वहां मूलयवृद्धि होती भी है तो दूसरी तरफ़ सुप्रीम लीडर के बजट से लोगों को साथ साथ उतनी ही राहत भी दी जाती है। वहां महिलायें कम्युनिटी प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं। प्रसव निःशुल्क हैं, साथ ही बच्चे के जन्म पर मां के खाते में कम से कम 20,000 रू का उपहार भी भेजा जाता है। प्रत्येक इलाज का 70% सरकार देती है, जबकि 30% मरीज़ देता है। चोरी, डकैती,बेईमानी,बलात्कार जैसे अपराध बिल्कुल नहीं है। चंदा या दान चोरी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहां रॉयल कल्चर या प्रोटोकॉल जैसी कोई चीज़ नहीं है। ईरान भिखारी रहित देश है। वहां के नियमानुसार पुलिस सूर्यास्त से सूर्योदय तक किसी अपराधी के घर में नहीं घुस सकती क्योंकि वह समय उसकी पत्नी और बच्चों का होता है। वहाँ की जेलें ख़ाली हैं, और अगर कोई अपराधी जेल जाता भी है, तो उसे जेल में काम दिया जाता है, जिसकी तंख़्वाह/मज़दूरी उसके घर भेजी जाती है ताकि उसके परिवार के लोग पैसों के अभाव में किसी अपराध में शामिल न हों।

ईरान में धर्म जाति जैसी कोई विसंगति नहीं है इसलिये कभी साम्प्रदायिक व जातीय दंगे नहीं होते। छुआछूत जादू टोना जैसी कोई प्रथा नहीं है। यहां विभिन्न धर्मों के मानने वाले व उनके अनेक पूजा स्थल हैं, धर्म के मामलों में सभी को पूरी आज़ादी है। यहां अध्यापकों को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है। घरेलू नौकर रखने का यहाँ चलन नहीं है। अपने सभी घरेलू काम स्वयं करने पड़ते हैं। इतने अंततर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद यहाँ के लोगों के चेहरों पर हंसी मुस्कान व संतोष नज़र आता है।

कोई भी व्यक्ति चिढ़ा कुढ़ा या ग़ुस्से में नज़र नहीं आता। ईरानियों के इसी स्वभाव हौसले,जज़्बे,कुर्बानी व उनके ईमान की वजह से ही दुनिया के तमाम देश जहाँ अमेरिका व इस्राईल से नफ़रत करने लगे हैं बल्कि वे ईरान से प्यार भी कर रहे हैं व उनका साथ भी दे रहे हैं। इन्हीं व इन जैसे अनेक कारणों की वजह से ही लगभग 50 वर्षों से वैश्विक प्रतिबंध झेलने व अमेरिका जैसी महाशक्ति से लोहा लेने वाला देश आज न केवल 'विजेता ' बनकर उभरा है बल्कि इसने विश्व की महाशक्तियों में भी अपना नाम दर्ज करवा लिया है।

बदलते मौसम का बढ़ता जोखिम

कभी भारत की पहचान समय पर आने वाले मानसून से होती थी। किसान आकाश में उमड़ते-घुमड़ते बादलों को देखकर भविष्य की समृद्धि का अनुमान लगा लेते थे। गाँवों की चौपालों से लेकर शहरों की गलियों तक वर्षा का स्वागत उत्सव की तरह होता था। लेकिन अब मौसम का यह भरोसा लगातार कमजोर पड़ता जा रहा है। कभी बादल आते हैं पर बरसते नहीं, कभी बिना चेतावनी के मूसलाधार वर्षा सब कुछ बहा ले जाती है और कभी लंबे समय तक आसमान सूना पड़ा रहता है। ऐसा लगता है मानो बादल भी इंसान से पूछ रहे हों—क्या तुमने प्रकृति के साथ न्याय किया है? आज जलवायु परिवर्तन केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं का विषय नहीं रह गया, बल्कि आम आदमी के जीवन का कठोर यथार्थ बन चुका है। ऋतुओं का क्रम बदल रहा है, तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है और वर्षा का स्वभाव असामान्य होता जा रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। यह वर्षों से प्रकृति के साथ किए गए हमारे असंतुलित व्यवहार का परिणाम है।

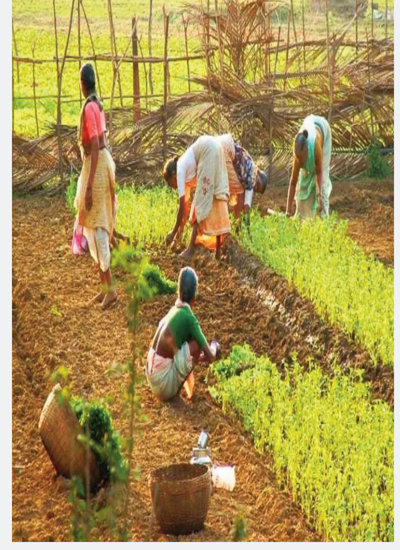

मनुष्य ने विकास की दौड़ में जंगलों को काटा, नदियों को प्रदूषित किया, तालाबों को पाट दिया और शहरों को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया। प्राकृतिक जल निकासी के मार्ग समाप्त हो गए। परिणाम यह हुआ कि जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सूखा पड़ता है और जहाँ अधिक होती है वहाँ बाढ़ विनाश का कारण बन जाती है। दोनों ही स्थितियाँ मानव निर्मित असंतुलन की कहानी कहती हैं। सबसे अधिक चिंता का विषय किसान है। खेती आज भी वर्षा पर बहुत हद तक निर्भर है। जब बादल समय पर नहीं आते, तो बीज मिट्टी में दम तोड़ देते हैं। किसान की मेहनत, उम्मीद और पूँजी तीनों दाँव पर लग जाती हैं। दूसरी ओर, यदि अत्यधिक वर्षा हो जाए तो तैयार फसल खेतों में ही नष्ट हो जाती है। ऐसे में कृषि केवल पेशा नहीं, बल्कि जोखिम का पर्याय बनती जा रही है।

जल संकट भी तेजी से गहराता जा रहा है। भूजल स्तर निरंतर नीचे जा रहा है। शहरों में पानी की आपूर्ति चुनौती बन रही है, जबकि गाँवों में कुएँ और तालाब सूखने लगे हैं। यदि वर्षा का जल सुरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में पानी को लेकर सामाजिक और आर्थिक संघर्ष बढ़ सकते हैं।

इस चुनौती का समाधान केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वर्षा जल संचयन, वृक्षारोपण, जल स्रोतों का संरक्षण, प्लास्टिक का सीमित उपयोग और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवनशैली अपनाना समय की आवश्यकता है। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को पौधारोपण, जल संरक्षण और स्थानीय पर्यावरण के संरक्षण से जोड़ना होगा। मीडिया, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी जन-जागरूकता की इस मुहिम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारतीय संस्कृति सदैव प्रकृति को पूजनीय मानती रही है। हमारे पर्व, व्रत और परंपराएँ जल, वृक्ष और धरती के संरक्षण का संदेश देती हैं। आधुनिक विकास तभी सार्थक होगा, जब उसमें पर्यावरणीय संतुलन भी शामिल हो। केवल आर्थिक प्रगति भविष्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बादलों से शिकायत करने के बजाय अपने व्यवहार का आत्ममंथन करें। यदि हम प्रकृति के साथ संतुलित संबंध स्थापित करेंगे, तो मौसम भी अपना स्वाभाविक स्वरूप पुनः प्राप्त करेगा। अन्यथा आने वाली पीढ़ियों को जल, अन्न और स्वच्छ वातावरण के लिए गंभीर संघर्ष करना पड़ेगा।

समय की पुकार स्पष्ट है—प्रकृति के साथ सहयोग ही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी सुरक्षा है। यदि आज हमने यह संदेश नहीं समझा, तो आने वाला कल केवल मौसम का नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व का भी सबसे कठिन इम्तिहान बन सकता है।

कांग्रेस की गलतियों के कारण देश का विभाजन हुआ: सीएम योगी

पीलीभीत (उप्र), एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए सोमवार को कहा कि देश का विभाजन कांग्रेस की गलतियों का परिणाम था और यदि उस समय नेतृत्व दृढ़ रहता तो विभाजन टाला जा सकता था।

पीलीभीत में 569 करोड़ रुपये की लागत वाली 63 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तथा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से 56 वर्ष पहले बांग्लादेश से निकाले गए प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप नागरिकता और पुनर्वास की सुविधा मिल रही है, जिसके लिए सभी को बधाई।

उन्होंने कहा कि यह उनके लिए पुनर्जीवन जैसा है। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस के पाप के कारण बांग्लादेश बना। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बनना आवश्यक नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया, पाकिस्तान का निर्माण सत्तालोलुपता का परिणाम था और यदि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व अडिग रहता तो मोहम्मद अली जिन्ना सफल नहीं हो पाते और भारत का विभाजन नहीं होता। योगी ने कहा कि यदि विभाजन नहीं हुआ होता तो इन गरीबों, बंगाली परिवारों को विस्थापित नहीं होना पड़ता। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी हिंदू को विस्थापित न होना पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश रक्षा विनिर्माण गलियारे (डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर) में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी किया जा रहा है।

समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया, उसके शासनकाल में अपराध और अराजकता को बढ़ावा मिला, जबकि वर्तमान सरकार रक्षा उत्पादन और विकास को आगे बढ़ा रही है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया, उनके (सपा) शासन में पूरा विकास सिर्फ सैफई तक सीमित था।

योगी ने उन पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब माफिया गले में तख्ती लगाए घूम रहा है कि मुझे शरण में ले लो। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब कुछ चंगा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं की हत्या हुई और लाखों लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़नी पड़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वर्षों तक इन विस्थापित परिवारों की सुध नहीं ली और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती रहीं।

उन्होंने कहा, ''दिल्ली और देश के विभिन्न राज्योंप में कांग्रेस और सपा ने आंदोलन किया था कि इनको (नागरिकता) प्रमाणपत्र नहीं मिलना चाहिए। इनका उद्देश्य ही क्याव है कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही तो इनकी तुष्टीकरण की नीति थी और यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा।

योगी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में विस्थापित हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया।

उन्होंने कहा कि नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद अब कोई भी इन लोगों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकता और न ही उन्हें पराया कह सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब इन विस्थापित परिवारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के सपनों को संवारने और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार मिल गया है।

फडणवीस प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताएं तो मैं समर्थन करूंगा : उद्धव

शिरडी, एजेंसी। शिवसेना (उबाठा) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'हितैषी' हैं और यदि फडणवीस प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रखते हैं तो वह उनका समर्थन करेंगे।

शिरडी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, अगर वह (फडणवीस) सोचते हैं कि मैं उनका दुश्मन हूं, तो बता दूं कि मैं उनका हितैषी हूं। मैं उनके मन की बात कर रहा हूं। ठाकरे ने दावा किया कि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे 2029 में फडणवीस प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल न हो सकें।

उन्होंने कहा, अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो मेरी पार्टी उसका समर्थन क्यों नहीं करेगी। ठाकरे ने हालांकि कहा कि अगर फडणवीस प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी की घोषणा करते हैं तो यह भाजपा में उनके लिए 'राजनीतिक आत्महत्या' करने जैसा होगा।उन्होंने कहा, अगर फडणवीस यह घोषणा करते हैं कि वह प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वह अपनी पार्टी में बने भी रह पाएंगे? शिरडी में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि जिस पार्टी में लोकसभा सदस्य भाऊसाहेब वाकचौरे गए हैं, वह पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वाकचौरे हाल ही में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हुए हैं और शिरडी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।

टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले में आरोपियों पर मकोका लगाने पर विचार : भुसे

मुंबई, एजेंसी।

महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को कहा कि वह आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाने की संभावना पर विचार कर रही है।

स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दिए गए उनके इस बयान के बीच विपक्ष पिछले सप्ताह हुए टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर भुसे के इस्तीफे की मांग कर रहा है।

भुसे ने घोषणा की कि सरकार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो टीईटी और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाएं ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित) माध्यम से आयोजित करने की रूपरेखा तैयार करेगी।

टीईटी प्रश्नपत्र लीक मामले पर सदन में वक्तव्य देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वे पुलिस हिरासत में हैं। मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है।

भुसे ने कहा, राज्य में 28 जून को होने वाली टीईटी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जा सकता है या नहीं।

मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर द्रमुक का प्रदर्शन

चेन्नई,एजेंसी। तमिलनाडु के मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री डी. शरथकुमार को कथित मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार करने और मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी की मांग करने वाले विपक्षी द्रमुक के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। द्रमुक के छात्र प्रकोष्ठ की ओर से शहर के एग्मोर स्थित राजारथिनम स्टेडियम के निकट आयोजित प्रदर्शन की अध्यक्षता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मा. सुब्रमणियन ने की। यह प्रदर्शन सोशल मीडिया पर वायरल हुए उस वीडियो के बाद आयोजित किया गया, जिसमें कथित तौर पर श्री शरथकुमार दो वर्ष पहले चेन्नई में आईपीएल मैच के दौरान सफेद रंग के पाउडर जैसी किसी वस्तु को तैयार करते दिखाई दे रहे हैं।

मिजोरम मंत्रिमंडल में फेरबदल की जरूरत नहीं : लालदुहोमा

आइजोल, एजेंसी।

मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की संभावना से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि उनके मंत्री अब अपने-अपने विभागों में पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं और व्यापक बदलाव की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है।

लालदुहोमा ने जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के पांच वर्षीय कार्यकाल का आधा समय पूरा होने के साथ ही मंत्रिमंडल में बड़े फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही थीं।

उन्होंने कहा, कई लोगों को इस समय बड़े फेरबदल की उम्मीद थी, लेकिन हमारे मंत्री कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अब जाकर अपने-अपने विभागों में पूरी तरह स्थापित हुए हैं। इसलिए हमें बड़े फेरबदल की जरूरत नहीं दिखती। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब कुछ दिन पहले उन्होंने मंत्री के. सपदांगा से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अपने पास ले लिया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच मतभेद की अटकलें लगाई जाने लगी थीं। लालदुहोमा ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय पहले ही जेडपीएम की राजनीतिक मामलों की समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया था और इसका किसी भी प्रकार के आंतरिक मतभेद से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अब तक लगभग 10 छोटे प्रशासनिक बदलाव कर चुकी है।

अनिल परब ने महाराष्ट्र के नगर निगमों में करोड़ों रूपये के भूमि घोटाले का लगाया आरोप

मुंबई,एजेंसी।

शिवसेना (यूबीटी) नेता एवं विधान परिषद सदस्य अनिल परब ने महाराष्ट्र के नासिक सहित राज्य के नगर निगमों में भूखंडों के अवैध उप-विभाजन और म्हाडा आवास परियोजनाओं के लिए आरक्षित भूमि की हेराफेरी से जुड़े एक बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। परब ने सोमवार को राज्य विधान परिषद में इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि साल 2013 से विकासकर्ताओं, स्थानीय अधिकारियों और नगर नियोजन विभाग की मिलीभगत से करोड़ों रूपये का घोटाला चल रहा है।

उन्होंने दावा किया कि नियमों से बचने के लिए 1981 के एक सरकारी परिपत्र का उल्लंघन करके भूमि के टुकड़ों का अवैध रूप से विभाजन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकासकर्ता म्हाडा आवास के लिए 20 प्रतिशत, खुले स्थानों के लिए 10 प्रतिशत और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए 5 प्रतिशत के अनिवार्य आरक्षण की आवश्यकताओं से बचने के लिए 4,000 वर्ग मीटर से छोटे भूखंड बना रहे हैं। परब ने कहा, 7/12 भूमि अभिलेख (सातबारा) में हेरफेर करके और आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना लेआउट मंजूरी प्राप्त कर ली जाती है। इन विकासकर्ताओं ने व्यवस्थित रूप से सार्वजनिक आरक्षण को मिटा दिया है।

विजयभास्कर ने विधायक पद से दिया इस्तीफा

चेन्नई,एजेंसी। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) के कद्दावर नेता और तमिलनाडु के पूर्व परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर ने सोमवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में 'एमआरवी' के नाम से मशहूर विजयभास्कर राज्य में 23 अप्रैल को हुए विधानसभा चुनावों में करूर विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार चुने गए थे। वह पहली बार 2016 में जीते थे और दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने उन्हें पहली बार मंत्री बनाया था। श्री विजयभास्कर 2021 में हालांकि यहां से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के वी. सेंथिलबालाजी से हार गए थे लेकिन इस चुनाव में जीत हासिल की थी।

गौरतलब है कि श्री विजयभास्कर उन 25 बागी विधायकों में से एक हैं।

नीमच के सोलर प्लांट से मिलेगी देश की सबसे सस्ती बिजली

नीमच, एजेंसी।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को मध्यप्रदेश में कुल 950 मेगावाट क्षमता वाली दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कहा कि इनमें शामिल नीमच सोलर पार्क में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का शुल्क संभवतः दुनिया में 'वैनिला सोलर' परियोजना की सबसे कम दर है। ऊर्जा क्षेत्र में 'वैनिला सोलर' शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाता है जिनमें केवल सौर पैनल के जरिये बिजली उत्पादन किया जाता है और बैटरी भंडारण जैसी अतिरिक्त सुविधाएं शामिल नहीं होतीं। जोशी ने एक समारोह में जिन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें नीमच का 500 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क और शाजापुर का 450 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क शामिल हैं। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे।

अधिकारियों ने बताया कि कुल 2,500 एकड़ पर निर्मित तीन इकाइयों वाले नीमच सोलर पार्क में उत्पादित बिजली की दर 2.14 रुपये, 2.149 रुपये और 2.15 रुपये प्रति यूनिट है।

जोशी ने उद्घाटन समारोह में कहा, नीमच सोलर पार्क में बड़ा गजब का काम हुआ है। जहां तक मुझे जानकारी है, 2.14 रुपये प्रति यूनिट सारे देश में नहीं, बल्कि सारी दुनिया में वैनिला सोलर परियोजना से बनने वाली बिजली की शायद सबसे कम दर है।

केंद्रीय मंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि मध्यप्रदेश 'हरित ऊर्जा का पावरहाउस' बन रहा है।

जोशी ने कहा कि प्रदेश की कुल 38 गीगावाट की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में से लगभग 12 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपेक्षा के अनुरूप राज्य की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए।

जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार के अध्ययन के अनुसार, प्रदेश में लगभग 55 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में 3.7 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है और 1.3 गीगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर काम जारी है।

उन्होंने कहा,अगर अगले दो वर्ष का लक्ष्य तय करके राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर कम से कम 10 गीगावाट तक पहुंचाया जाता है, तो बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी। इससे राज्य के किसानों व उद्योगों को फायदा होगा और नये औद्योगिक निवेश की रफ्तार तेज होगी।

सार समाचार

कविता ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर उठाए सवाल

हैदराबाद,एजेंसी। तेलंगाना रक्षण सेना (टीआरएस) की अध्यक्ष के कविता ने सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के विधानसभा चुनाव क्षेत्र कोडंगल में हजारों फर्जी और अंतर-राज्यीय मतदाताओं की मौजूदगी का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता बरतने की मांग की है।

महाराष्ट्र विधान परिषद के उप-सभापति का चुनाव एक जुलाई को

मुंबई,एजेंसी। महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति पद का चुनाव आगामी एक जुलाई को दोपहर 13.00 बजे होगा। विधान परिषद के सभापति राम शिंदे ने इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही खाली पद को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। महाराष्ट्र के उच्च सदन में महायुति गठबंधन के पास बहुमत होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि यह पद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मिलेगा। सत्ताधारी गठबंधन के बीच मौजूदा सत्ता-साझाकरण व्यवस्था के तहत जहां सभापति का पद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास है, वहीं गठबंधन का संतुलन बनाए रखने के लिए उप-सभापति का पद शिवसेना (शिंदे गुट) के लिए तय किया गया है। राजनीतिक हलकों में शिवसेना के उम्मीदवार को लेकर अटकलें तेज हैं। वरिष्ठ नेता डॉ. नीलम गोर्हे पहले भी उप-सभापति रह चुकी हैं।

नसरापुर दुष्कर्म-हत्या मामले में पुणे की अदालत ने सुनाई मौत की सजा

पुणे,एजेंसी।

त्वरित न्याय की नयी मिसाल पेश करने वाले ऐतिहासिक फैसले में पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय ने आज पुणे जिले के नसरापुर में साढ़े तीन वर्ष की बच्ची के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के मामले में भीमराव कांबले (65) को मौत की सजा सुनाई। इस अपराध को 'दुर्लभ से दुर्लभतम' बताते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया, जिससे पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख देने वाले इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल सका।

इस ऐतिहासिक फैसले का राजनीतिक जगत के तमाम नेताओं ने पुरजोर स्वागत किया है और इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा, अदालत ने बेहद उचित फैसला सुनाया है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। ऐसे अमानवीय अपराध हमारे समाज में सुरक्षा की बुनियाद को कमजोर करते हैं, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो संदेश में कहा कि यह फैसला कानून के शासन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और पीड़ित परिवार के लिए 'न्याय की बड़ी जीत' है। उन्होंने कहा कि एक मई को हुई इस घटना के तुरंत बाद उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि सरकार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। शिंदे ने कहा, हमने संकल्प लिया था कि जब तक अपराधी को कानून के तहत अधिकतम सजा नहीं मिल जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज अदालत के फैसले के साथ राज्य सरकार ने उस प्रतिबद्धता को पूरा किया है।

शून्य-सहिष्णुता की नीति पर जोर देते हुए उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा, राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस तरह के अमानवीय अपराधों के लिए कोई माफी नहीं है। नसरापुर मामले में इतनी जल्दी दोषसिद्धि होना इस बात की मिसाल है कि कैसे प्रशासन और न्यायपालिका रिकॉर्ड समय में न्याय देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी टिप्पणी में कहा, यह घटना एक काला अध्याय बनकर रहेगी।

मृत्युदंड हालांकि इस मामले में बिल्कुल सही कानूनी जवाब है, लेकिन हमें व्यवस्थागत बदलावों के लिए अपनी आवाज बुलंद रखनी होगी।

मीरवाइज ने नजरबंद किये जाने का लगाया आरोप

श्रीनगर,एजेंसी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने श्रीनगर के बेमिना इलाके में इमामबाड़ा में धार्मिक सभा में जाने से पहले नजरबंद किए जाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि शिया-सुन्नी एकता और हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों के प्रति साझा सम्मान के तौर पर आगा सैयद हादी के निमंत्रण पर मीरवाइज को इमामबाड़ा बेमिना में प्रवचन देना था।

इस यात्रा का मकसद उनके महान बलिदान को श्रद्धांजलि देना और कर्बला से प्रेरित एकता, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाना था। मीरवाइज ने कहा कि उन्हें नजरबंद कर दिया गया है और सभा में शामिल होने से रोका गया है।

सीमा क्षेत्र में एक और पाकिस्तानी ड्रोन नेटवर्क का खुलासा

श्रीगंगानगर, एजेंसी।

राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के समेजा कोठी थाना क्षेत्र पिछले लंबे समय से भारत-पाकिस्तान तस्करों का पसंदीदा स्थल बना हुआ है। यहां पाकिस्तानी तस्करों द्वारा ड्रोन से गिराये जाने वाले हेरोइन और हथियारों के पैकेटों को स्थानीय संपर्कों के जरिए पंजाब के तस्कर उठाते रहे हैं।

अब इस पूरे नेटवर्क का एक और बड़ा हिस्सा सामने आया है। खुफिया पुलिस श्रीगंगानगर के दल ने समेजा कोठी थाना क्षेत्र के बरूवाला गांव के तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके रायसिंहनगर पुलिस के हवाले कर दिया है।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रणजीत सिंह (28),विकासदीप उर्फ विक्की (26) और सुखविंदर सिंह उर्फ छिदासिंह उर्फ टहल सिंह (22) शामिल हैं। ये तीनों पाकिस्तानी तस्करों के साथ मिलकर ड्रोन से हेरोइन और हथियार मंगवाने के नेटवर्क में सक्रिय थे।

रायसिंहनगर पुलिस इस वर्ष 18 अप्रैल को समेजा कोठी थाना क्षेत्र के चक 4-बीडब्ल्यूएसएम में किसान आत्माराम के खेत में मिले करीब 760 ग्राम हेरोइन के पैकेट के मामले की जांच कर रही थी।

इस मामले की जांच सीआईडी (जॉन) को भी शामिल किया गया। करीब दो महीने की गहन छानबीन के बाद सीआईडी को पता चला कि यह हेरोइन पैकेट बरूवाला गांव के इन तीनों आरोपियों ने पाकिस्तानी तस्करों से व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगवाई थी।

आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ जनहित याचिका खारिज

जबलपुर,एजेंसी।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं अजाक्स के कथित प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के विरुद्ध दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका में मांगी गई राहतें कानूनी रूप से स्वीकार नहीं की जा सकतीं तथा यदि किसी मामले में कार्रवाई बनती है तो कानून अपना कार्य करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अभिषेक दुबे ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2025 में अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज के संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। याचिका में उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा ब्राह्मण समाज के हित में दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा कि जिन धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी, उस संबंध में पहले से ही मामला दर्ज है, इसलिए इस संबंध में अलग से कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

खंडपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करना संबंधित प्रशासनिक प्राधिकार का अधिकार क्षेत्र है।

बैठक के दौरान महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'नवचेतना' प्रारंभिक बाल विकास जांच कार्यक्रम पर भी प्रस्तुति दी गई

सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और जनहितैषी बनाएं अधिकारी: नायडू

अमरावती, एजेंसी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ, सरल और जनहितैषी बनाने का निर्देश दिया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय स्थित रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी (आरटीजीएस) केंद्र में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों से सेवा वितरण प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित बनाने को कहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक हितैषी बनाने तथा सेवा वितरण प्रणाली को सरल एवं सुव्यवस्थित करने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सरकार ने 11 श्रेणियों की सेवाओं से शुरुआत करते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं।

नायडू ने अधिकारियों को लोक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने तथा इसे आम लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने सुझाव दिया कि लोगों को ऑनलाइन और 'मन मित्र' व्हाट्सऐप गवर्नेंस मंच के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके तहत आवाज के रूप में संदेश भेजकर भी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया जाए।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य में लगभग 3,000 स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। इस पर नायडू ने तीन महीने के भीतर इन समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।

बैठक के दौरान महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा संचालित 'नवचेतना' प्रारंभिक बाल विकास जांच कार्यक्रम पर भी प्रस्तुति दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का आकलन किया जाता है तथा अब तक राज्य में लगभग 34,000 बच्चों की जांच की जा चुकी है।

सरकारी वेबसाइट के अनुसार 'नवचेतना' जन्म से तीन वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए गतिविधि-आधारित पाठ्यक्रम है।

अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों की जांच के साथ-साथ टीमों द्वारा घर-घर जाकर भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रमुख समस्याओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनका तत्काल समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली को और प्रभावी बनाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की गई है। बाद में नायडू ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ आरटीजीएस केंद्र का दौरा किया।

भाजपा पहले अपने 11 वर्ष आठ महीने का हिसाब दे: राव नरेंद्र सिंह

भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, युवाओं की भर्तियों, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है

चंडीगढ़, एजेंसी।

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं के कांग्रेस पर दिए जा रहे बयानों को तथ्यों से परे, निराशा से प्रेरित और जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास करार देते हुए कहा कि भाजपा पहले अपने 11 वर्ष आठ महीनों के कार्यकाल का हिसाब दे। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सिंह ने कहा कि भाजपा ने हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बजाय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और कुशासन की ओर धकेला है। जनता अब प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि जवाबदेही और परिणाम चाहती है।

उन्होंने कहा कि जिस भाजपा शासन में हरियाणा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटालों, किसानों की

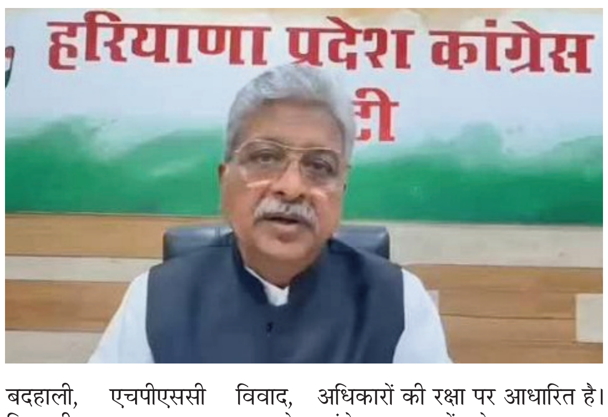

बदहाली, एचपीएससी विवाद, बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बढ़ते अपराध, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा हो, उसे कांग्रेस के नेतृत्व और विचारधारा पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा संविधान, सामाजिक न्याय, समान अवसर, लोकतंत्र, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, युवाओं और गरीबों के अधिकारों की रक्षा पर आधारित है। कांग्रेस सरकारों ने सूचना का अधिकार, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार और आर्थिक विकास जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय देश को दिए।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, युवाओं की भर्तियों, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है तथा प्रचार और झूठे नैरेटिव की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और हरियाणा सरकार ईंधन बचाने की अपील कर रहे हैं तथा 30 सितंबर तक रैलियों, रोड शो और बड़े सार्वजनिक आयोजनों को लेकर प्रतिबंधात्मक निर्देश जारी किए गए हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के स्वागत में बड़े-बड़े काफिलों और समारोहों का आयोजन किया जा रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकारी निर्देश जनता के लिए हैं तो क्या वे भाजपा नेताओं पर लागू नहीं होते। सिंह ने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंचकूला से जुड़े सरकारी धन घोटाले ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय विपक्ष पर आरोप लगाने में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश का युवा भर्ती परीक्षाओं, पेपर लीक और रोजगार को लेकर परेशान है। किसान अपनी फसल का उचित मूल्य पाने के लिए संघर्ष कर रहा है।

अपराध बढ़ रहे हैं, महंगाई से आम जनता प्रभावित है, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है तथा बढ़ते कर्ज के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। श्री राव ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 11 वर्ष 8 महीने के कार्यकाल में हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के बजाय बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक बदहाली और कुशासन की ओर धकेला है। जनता अब प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट नहीं, बल्कि जवाबदेही और परिणाम चाहती है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा को कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय यह बताना चाहिए कि पिछले वर्षों में युवाओं को कितनी पारदर्शी नौकरियां मिलीं।

कबीर के विचारों का प्रभाव है मेरे जीवन और वाणी पर: साय

रायपुर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि उनके जीवन और वाणी पर संत कबीर के विचारों का गहरा प्रभाव है तथा प्रदेश की धरती पर कबीर साहब का विशेष आशीर्वाद रहा है।

साय सोमवार को रायपुर जिले के सोनपैरी स्थित असंग देव कबीर आश्रम में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल गहलोत और मुख्यमंत्री साय ने आश्रम परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ की धरती पर कबीर साहब का विशेष आशीर्वाद है और पूरे प्रदेश में कबीरपंथ के अनुयायी बड़ी संख्या में

हैं। मेरा बचपन भी कबीरपंथ के करीब बीता है। मेरे जीवन और मेरी वाणी पर कबीर जी के विचारों का गहरा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि पूर्व की रमन सरकार के समय कवर्धा का नाम बदलकर कबीरधाम रखा गया था तथा कबीरदास की निडरता समाज के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कार्यभार संभाले अभी ढाई वर्ष हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ₹मोदी की गारंटी₹ को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27 लाख लोगों को लाभ मिला है, जबकि उनकी सरकार के कार्यकाल में 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं और वर्तमान में देश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री आवास का निर्माण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। साय ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई है तथा तीन हजार से ज्यादा आत्मसमर्पित नक्सलियों को भी पीएम आवास की सुविधा दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि विशेष अनुसूचित जनजाति के 32 हजार लोगों को आवास उपलब्ध कराया गया है। साथ ही गरीबों को आवास, महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत किश्तें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ₹विकास और विरासत₹ के संकल्प के साथ कार्य कर रही है तथा मठ-मंदिरों के विकास के साथ राम लला अयोध्या दर्शन योजना का भी संचालन किया जा रहा है।

सार समाचार

अल्मोड़ा में सड़क हादसे में चार लोगों की मौत

अल्मोड़ा,एजेंसी। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब छह लोगों को लेकर जा रही एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर करीब 20 से 25 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में गंभीर रुप से घायल दो लोगों को एयर एंबुलेंस से हल्द्वानी रेफर किया गया है। हादसा ग्राम बलिया-बैगनिया रोड पर हुआ। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त सभी लोग कार से ग्राम विशौद बैगनिया से अपने गांव बलिया लौट रहे थे। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष प्रमोद पाठक पुलिस टीम और रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी को खाई से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगड़ा पहुंचाया गया।

किशनगंज में तीन करोड़ की हेरोइन के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

किशनगंज,एजेंसी। बिहार के किशनगंज जिले में रामपुर चेक पोस्ट के समीप पुलिस ने डेढ़ किलोग्राम हेरोइन के साथ तीन अंतरराज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर-वन) खुसरू सिराज ने सोमवार को बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर उनके नेतृत्व में जिला आसूचना इकाई, एएनटीएफ और किशनगंज थाना पुलिस की संयुक्त विशेष टीम गठित की गई थी।उन्होंने बताया कि रामपुर चेक पोस्ट के समीप विशेष वाहन जांच अभियान के दौरान मालदा (पश्चिम बंगाल) से आ रही एक बस से उतरे दो व्यक्ति पहले से मौजूद एक अन्य व्यक्ति से मिले। पुलिस को देखकर तीनों भागने लगे, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया।

एचआरएमएस की जिम्मेदारी दो विभागों में बांटी

चंडीगढ़,एजेंसी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए संचालित हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। मानव संसाधन विभाग (कॉमन कैडर-2) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब एचआरएमएस के विभिन्न मॉड्यूल का प्रशासनिक स्वामित्व दो विभागों के बीच विभाजित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत सेवा संबंधी मॉड्यूल मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) के अधीन रहेंगे, जबकि वेतन और वित्तीय मामलों से जुड़े मॉड्यूल वित्त विभाग (ट्रेजरी एवं अकाउंट्स) संचालित करेगा। सरकार के अनुसार, एचआरएमएस पोर्टल में किसी भी प्रकार के तकनीकी बदलाव, संशोधन, नई सुविधा जोड़ने या नया मॉड्यूल विकसित करने से जुड़े प्रस्ताव अब सीधे संबंधित विभाग को भेजे जाएंगे।

मुरैना का सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम युगांतरकारी : सीएम डॉ. यादव

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नए आयाम प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुरैना की सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना युगांतरकारी है। इस परियोजना में मात्र दो रुपए 70 पैसे प्रति यूनिट की प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हुई है जो देश में अब तक की न्यूनतम दर और इस श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूर्व राष्ट्रीय मानक से भी कम है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार देर शाम भोपाल में देश में अपने तरह की अनूठी 440 मेगावॉट मुरैना सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना के पावर परचेज एग्रीमेंट कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषकर चंबल के निवासियों के लिए यह बधाई देने का विषय भी है। परियोजना के विशेषता इसका

अभिनव बैटरी मॉडल है, जिसमें एक बैटरी का रोजाना दो बार इस्तेमाल करना संभव होगा। इसके साथ ही नीमच और शाजापुर सौर पार्कों को लोकार्पण इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एतिहासिक उपलब्धि है।

कार्यक्रम में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह एग्रीमेंट और 2 सौर पार्कों का लोकार्पण नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय घटना है। यह एग्रीमेंट निरंतर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाते और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के पश्चात इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एक नई उपलब्धि है।

कार्यक्रम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय नीरज मंडलोई, अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम के एमडी अमित तोमर सहित एग्रीमेंट से जुड़े संस्थान के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी क्षेत्रों में नई वैज्ञानिक खोजों के कारण नागरिकों को बेहतर लाभ दिलवाने की पहल देश में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पानी के बंटवारे का 20-25 वर्ष पुराना विवाद समाप्त करवाने में पूरा सहयोग किया। उनके मार्गदर्शन में पार्वती- कालीसिंध-चंबल अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजना मंजूर हुई, जिसमें राजस्थान भी लाभान्वित होगा और मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा से लेकर 13 जिलों के वृहद क्षेत्र को समृद्धि का लाभ मिलेगा। इसी तरह नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, कोल, हाइड्रो के साथ सोलर एनर्जी के कई प्रकार उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना सोलर ऊर्जा भण्डारण की परियोजना वर्तमान दौर में ऊर्जा उत्पादन की नई संभावनाओं को क्रियान्वित करने का ठोस उदाहरण है।

भीषण सड़क हादसे में सैनिक समेत चार लोगों की मौत

जालंधर,एजेंसी। पंजाब में जालंधर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार तड़के सड़क हादसे में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गयी, जबकि दूसरी कार में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गये।

मृतकों में एक सैनिक, उसकी पत्नी, दो वर्षीय पुत्र और एक अन्य महिला शामिल हैं।

यह हादसा सुबह करीब 5:40 बजे किशनगढ़ के पास जौहल ढाबे के नजदीक हुआ। जानकारी के अनुसार, होशियारपुर निवासी परिवार मारुति बलेनो में सवार होकर श्री हजूर साहिब के दर्शन के लिए जा रहा था।

इसी दौरान कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गयी और सामने से आ रही क्रेटा से सीधी भिड़ंत हो गयी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बलेनो कार के परखच्चे उड़ गये और उसमें सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी।

शेखावाटी को यमुना जल मिलने का ऐतिहासिक समझौता: तिवाड़ी

जयपुर, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं सांसद घनश्याम तिवाडी ने यमुना जल समझौते को राजस्थान के लिए विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र के तीन प्रमुख जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू के लिए ऐतिहासिक समझौता बताया है। तिवाड़ी ने इस समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि शेखावटी क्षेत्र लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहा था।

अब यमुना नदी के पानी मिलने से क्षेत्र की जल समस्या से निजात मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री सी.आर.पाटिल की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

उन्होंने बताया कि श्री शर्मा ने लगातार इस कार्य के लिए प्रयासरत रहे, उसी का परिणाम है कि अब शेखावाटी क्षेत्र को 1975 क्यूसेक यमुना जल उपलब्ध हो सकेगा, जो पांच बीसलपुर बांध जितना पानी है। इस परियोजना के तहत तीन प्रमुख बांधों की पहचान की गयी है, जिनमें पानी का संग्रहण किया जाएगा। इनमें माछल बांध भी शामिल है, जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किये हैं और राज्य सरकार ने इसके विकास कार्य को गति दी है।

रायपुर में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए 80 मकान हटाए गए

रायपुर, एजेंसी।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के माना क्षेत्र स्थित नकटी गांव में प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के लिए सोमवार को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए 80 मकानों को ध्वस्त कर दिया। हटाए गए मकानों में प्रधानमंत्री आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित 32 आवास भी शामिल हैं। कार्रवाई के मद्देनजर रविवार देर रात से ही क्षेत्र में एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। सोमवार सुबह प्रशासनिक अमला जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंचा तो कई ग्रामीण विरोध में मशीनों के सामने खड़े हो गए।

इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की तथा तीखी नोकझोंक भी हुई। तनावपूर्ण माहौल के बीच एक बच्ची ने रोते हुए बताया कि कार्रवाई की आशंका के कारण सुबह घर में खाना नहीं बन पाया और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कार्रवाई के विरोध में प्रभावित

ग्रामीणों ने धरना भी दिया। उनका कहना था कि दो दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि बारिश के मौसम में किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने आज सुबह कार्रवाई शुरू कर दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें झूठा आश्वासन दिया गया। कार्रवाई के दौरान कई परिवार अपने घरेलू सामान के साथ मकानों के बाहर बैठे दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग टूटे हुए मकानों के मलबे के पास ही डटे रहे। एक बुजुर्ग मासूम बच्चे को गोद में लेकर मलबे के पास बैठे नजर आए।

अति सुरक्षित जेल में डकैत जगन गुर्जर की गला घोंट कर हत्या

अजमेर,एजेंसी। राजस्थान में अजमेर में अति सुरक्षित समझी जाने वाली अजमेर जेल में बंद कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की गला घोंट कर हत्या कर दी गयी। जेल के बैरक में उसके साथ ही बंद अन्य कैदी विष्णु गुर्जर ने गमछे से गला घोट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलते ही जेल और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और अतिरिक्त कलेक्टर मौके पर पहुंचे। अति सुरक्षित इस जेल में इस तरह के मामले ने कई गंभीर सवालों को पैदा कर दिया है, लेकिन पुलिस का दावा है कि यह मामला किसी तरह का गिरोह संघर्ष का नहीं है। जबकि इस पूर्व भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं।

अग्रवाल ने बताया कि यह घटना आज दोपहर हुई। फिलहाल जगन का शव शवगृह में भिजवा दिया गया है।

महात्मा गांधी के नाम शुरू हो नई योजना: दीपिका पांडेय सिंह

रांची, एजेंसी।

झारखंड की ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राष्ट्रीय मंच पर महात्मा गांधी के नाम योजना संचालित करने की मांग रखी है। श्रीमती सिंह ने कहा कि वी बी ग्राम जी योजना से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को महात्मा गांधी के नाम से नई जनहित की योजना आरंभ करनी चाहिए। दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन झारखंड राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रेजेंटेशन में मंत्री ने 125 दिन काम का प्रयाप्त बजट, स्ट्रांग फेब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वाले आवास निर्माण से लेकर मनरेगा के बकाया भुगतान सहित अन्य मुद्दों को मजबूती से रखा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के सुझाव पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया है। दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में वी बी ग्राम जी योजना का मुद्दा छाया रहा। 'विकसित ग्रामीण भारत'

निर्माण की सोच को लेकर देश भर से जुटे ग्रामीण विकास मंत्रियों ने अपने - अपने सुझाव दिए। श्रीमती सिंह ने योजना में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60 - 40 की हिस्सेदारी ने परेशानी बढ़ा दी है। इस निर्णय से झारखंड जैसे राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

श्रीमती सिंह ने कहा कि राज्य के मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की बजाय 125 दिन काम देने के निर्णय को लेकर विभाग की क्या तैयारी है? क्या इसके लिए विभाग के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है? उन्होंने कहा कि समय के साथ केंद्र सरकार साल दर साल मनरेगा के बजट में कटौती कर रही है। फिर सरकार मजदूरों को 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार देने का कैसे दावा कर रही है। श्रीमती सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ा कर 2 लाख रुपए करने की मांग रखी है।

उन्होंने कहा कि आवास निर्माण की राशि को बढ़ाना समय की मांग और लाभुकों की जरूरत है। श्रीमती सिंह ने ससमय आवास निर्माण की योजना को पूर्ण करने के लिए स्ट्रांग फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर वाले आवास निर्माण का सुझाव दिया है। इस योजना में लाभुकों को आवास निर्माण के लिए एक मुश्त राशि भुगतान की बात कही गई है। ऐसा करने से आवास निर्माण में हो रही देरी के साथ कई अन्य तरह की अड़चनों से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही अबुआ आवास योजना के निर्माण में मनरेगा के तहत 90 दिनों का मजदूरी भुगतान की मांग की मंत्री के द्वारा रखी गई। फैब्रिकेटेड आवास निर्माण के सुझाव से केंद्रीय मंत्री भी सहमत नजर आए।

सिंह ने केंद्र सरकार के समक्ष मनरेगा के मद में बकाया राशि भुगतान का मुद्दा फिर एक बार उठाया। वर्तमान में झारखंड राज्य का केंद्र सरकार के पास मनरेगा के मटेरियल मद में करीब 900 करोड़ रुपए का बकाया है। मनरेगा मटेरियल की राशि लंबित होने की वजह से योजना पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा हमेशा से रोजगार का एक मात्र साधन रहा है। कोरोना काल में मनरेगा से संचालित योजनाओं ने ग्रामीण मजदूरों को रोजगार से जोड़े रखा। ऐसे में केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग से वी बी ग्राम जी योजना शुरू होने से पहले मनरेगा के बकाया राशि भुगतान का अनुरोध किया गया है।

लगभग 62.33 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नगर की पार्किंग समस्या का समाधान करेगा

धामी ने दी चम्पावत को विकास और स्वास्थ्य की बड़ी सौगात

चम्पावत,एजेंसी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चम्पावत को विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी सौगात देते हुए 164 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 123.79 करोड़ रुपये की 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ ही करीब छह करोड़ की लागत से स्थापित अत्याधुनिक एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि चम्पावत को उत्तराखंड का मॉडल जिला बनाना उनका संकल्प है और राज्य सरकार सीमांत क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने 27.79 करोड़ रुपये की

लागत से पूर्ण हुई आठ विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 96 करोड़ रुपये की लागत से नौ नई योजनाओं का शिलान्यास किया।

इस दौरान लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत से विकसित जिम कॉर्बेट ट्रेल का उद्घाटन तथा रोडवेज बस स्टेशन परिसर में बनने वाले आधुनिक सिटी सेंटर का भूमि पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि लगभग 62.33 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला बहुमंजिला पार्किंग एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नगर की पार्किंग समस्या का समाधान करेगा और स्थानीय व्यापार को नई गति देगा। धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल भवन और सड़कें बनाना नहीं बल्कि ऐसा चम्पावत विकसित करना है जहां युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, किसानों को समृद्धि और व्यापारियों को नए अवसर मिलें।

उन्होंने बताया कि जिला में महिला प्रौद्योगिकी पार्क, आधुनिक पुस्तकालय, ज्ञान केंद्र, ओपन जिम, कृषि महाविद्यालय, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और आधुनिक साइंस सेंटर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी और विरासत भी के मंत्र के अनुरूप मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत पूर्णागिरि धाम, शारदा कॉरिडोर, गोल्ज्यू कॉरिडोर और मां वाराही धाम का विकास किया जा रहा है, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने जिला चिकित्सालय चम्पावत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत आईसीआईसीआई फाउंडेशन फॉर इन्क्लूसिव ग्रोथ के सहयोग से करीब छह करोड़ रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक एमआरआई मशीन का लोकार्पण किया।

उन्होंने कहा कि अब चम्पावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल और आसपास के सीमांत क्षेत्रों के लाखों लोगों को एमआरआई जांच के लिए हल्द्वानी या अन्य बड़े शहरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। मस्तिष्क, रीढ़, नसों, जोड़ों, कैंसर और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की जांच अब स्थानीय स्तर पर ही संभव होगी, जिससे समय पर उपचार मिल सकेगा।

पंजाब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए जारी किए 1,583 करोड़ रुपये

चंडीगढ़,एजेंसी।

पंजाब सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए अब तक 1,583 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सोमवार को बताया कि इस राशि से राज्य के बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। डॉ. कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पारदर्शी और प्रभावी ढंग से प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए सामाजिक सुरक्षा केवल एक बजटीय प्रावधान नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों के सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन की गारंटी है। डॉ कौर ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के तहत रिकॉर्ड 6,131.91 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिससे राज्य के लगभग 36 लाख लाभार्थियों को नियमित वित्तीय सहायता मिलेगी। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक 1,048 करोड़ रुपये वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजे जा चुके हैं। इसके अलावा 535 करोड़ रुपये से अधिक की राशि विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं आश्रित बच्चों तथा दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जारी की गयी है।

एलए ओलंपिक गेम्स में छाएगा क्रिकेट, 6-6 टीमें लेंगी हिस्सा

आईओसी ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है

नई दिल्ली, एजेंसी।

128 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी की दिशा में सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के पुरुष और महिला क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इस नई प्रणाली में दोनों प्रतियोगिताओं के लिए अलग-अलग क्वालिफिकेशन तरीके निर्धारित किए गए हैं। इस मंजूरी से यह सुनिश्चत हो गया है कि एलए28 में पुरुषों और महिलाओं के टी20 टूर्नामेंट में छह-छह टीमें हिस्सा लेंगी और प्रत्येक टीम में अधिक से अधिक 15 खिलाड़ी शामिल होंगे।

साल 1900 में आयोजित पेरिस ओलंपिक में क्रिकेट को पहली और इकलौती बार शामिल किया गया था, जिसके बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी में कुल 180 एथलीट (90 पुरुष और 90 महिलाएं) हिस्सा लेंगे। आईएसी और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की तरफ से संयुक्त रूप से जारी क्वालिफिकेशन सिस्टम से पता चलता है कि भले ही दोनों टूर्नामेंट्स में छह-छह टीमें होंगी, लेकिन पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स के लिए क्वालिफिकेशन के तरीके काफी अलग होंगे। पुरुषों के टूर्नामेंट के लिए, चार टीमें सीधे आईसीसी मेंस टी20 टीम रैंकिंग के जरिए क्वालीफाई करेंगी।

हालांकि, क्वालिफिकेशन सिर्फ टॉप चार रैंकिंग वाली टीमों से तय नहीं होगा। इसके बजाय, 31 दिसंबर 2026 को क्वालिफिकेशन विंडो खत्म होने पर चार अलग-अलग महाद्वीपों की चार सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य नेशनल ओलंपिक कमेटियां सीधे ओलंपिक में जगह पक्की करेंगी। लॉस एंजिल्स गेम्स के मेजबान के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स को जगह मिलेगी, बशर्ते वे क्वालिफिकेशन अवधि के दौरान किसी भी समय आईसीसी मेंस टी20 रैंकिंग में टॉप-15 में रहने की आईसीसी की न्यूनतम योग्यता शर्त को पूरा करें।

पुरुषों के लिए छठी और आखिरी जगह का फैसला 'फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट' (एफओजीक्यूटी) के जरिए होगा, जिसमें शेष एक स्थान के लिए अगली आठ सबसे ऊंची रैंकिंग वाली योग्य टीमें मुकाबला करेंगी, जिन्होंने पहले क्वालीफाई नहीं किया है। दूसरी तरफ, महिलाओं का क्वालिफिकेशन सिस्टम एक अलग मॉडल पर आधारित है। चार सीधे क्वालीफायर तय करने के लिए आईसीसी रैंकिंग का इस्तेमाल करने के बजाय, आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 मुख्य क्वालीफाइंग इवेंट होगा।

टूर्नामेंट के आखिर में चार अलग-अलग महाद्वीपों की सबसे अच्छी रैंकिंग वाली योग्य टीमें एलए28 के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगी। पुरुषों के इवेंट की तरह, मेजबान यूएसए को भी स्वतः प्रवेश मिलेगा, बशर्ते वे क्वालिफिकेशन पीरियड के दौरान टॉप 15 में रहने की न्यूनतम रैंकिंग की शर्त पूरी करें। अंतिम स्थान का फैसला 'फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट' के जरिए किया जाएगा, जिसमें अगली आठ सबसे अच्छी रैंकिंग वाली योग्य टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्होंने पहले क्वालीफाई नहीं किया है।

क्वालिफिकेशन सिस्टम का एक अहम पहलू वेस्टइंडीज से जुड़ा है। हालांकि, कैरेबियाई टीम आईसीसी इवेंट्स में एक संयुक्त टीम के तौर पर खेलती है, लेकिन आईओसी इसे 'नेशनल ओलंपिक कमिटी' के तौर पर मान्यता नहीं देता, इसलिए यह ओलंपिक गेम्स में एक इकाई के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकती। अगर वेस्टइंडीज 'फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट' के लिए योग्य टीमों में जगह बनाती है, तो आईसीसी कैरेबियाई देशों के बीच एक क्षेत्रीय क्वालीफाइंग टूर्नामेंट आयोजित करेगा, जिसका विजेता अंतिम टिकट हासिल करेगा।

क्वालिफिकेशन के मकसद से सिर्फ ओलंपिक-मान्यता प्राप्त 'नेशनल ओलंपिक कमिटी' की रैंकिंग पर ही विचार किया जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन के मामले में, क्रिकेट क्वालिफिकेशन में सिर्फ इंग्लैंड ही ब्रिटिश ओलंपिक दल का प्रतिनिधित्व करेगा। क्वालिफिकेशन टाइमलाइन के मुताबिक, महिलाओं की क्वालिफिकेशन प्रक्रिया असल में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के साथ शुरू होगी, जो 12 जून से 6 जुलाई 2026 तक होना है। वहीं, पुरुषों की क्वालिफिकेशन रैंकिंग 31 दिसंबर 2026 को बंद हो जाएगी।

जबकि ग्लोबल क्वालीफायर में जगह तय करने के लिए इस्तेमाल होने वाली महिलाओं की रैंकिंग 1 मार्च 2027 को पूरी होगी। पुरुषों और महिलाओं दोनों के 'फाइनल ओलंपिक ग्लोबल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट' की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है।

आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने इस घटनाक्रम को खेल के लिए एक ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा, ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट की वापसी हमारे खेल के लिए एक ऐतिहासिक पल है और दुनिया के सामने क्रिकेट का बेहतरीन रूप दिखाने का एक शानदार मौका है। क्वालिफिकेशन के इस तरीके की पुष्टि लॉस एंजिल्स 2028 की दिशा में एक अहम कदम है। उनका मानना है कि ओलंपिक मूवमेंट में वापसी से क्रिकेट की ग्लोबल पहुंच बढ़ाने का एक बेमिसाल मौका मिला है।

दक्षिण कोरिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद होंग ने इस्तीफा दिया

मेक्सिको सिटी,एजेंसी। होंग म्युंग-बो ने रविवार को दक्षिण कोरिया के मैनेजर का पद छोड़ दिया, क्योंकि टीम वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज तक नहीं पहुंच पाई। दक्षिण कोरिया ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर रहा, उसने अपना पहला मैच चेकिया के खिलाफ जीता था, लेकिन फिर मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका से हार गया।

होंग ने कहा, मैं उन लोगों से दिल से माफी मांगना चाहता हूं जिन्होंने कोरियन फुटबॉल को पसंद किया है और हमेशा नेशनल टीम को सपोर्ट किया है।

आज, मैं दक्षिण कोरिया की नेशनल फुटबॉल टीम के हेड कोच का पद छोड़ना चाहता हूं।

यह रोल स्वीकार करना मेरे लिए कभी आसान फैसला नहीं था। हालांकि, एक बार जब मैंने यह फैसला कर लिया, तो मैंने किसी और वजह के बारे में नहीं सोचा। मेरा मानना था कि मेरा एकमात्र काम मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी को आखिर तक पूरा करना है।

दक्षिण अफ्रीका को हराकर कनाडा ने राउंड ऑफ 16 में बनाई जगह

इंग्लवुड, एजेंसी।

स्टीफन यूस्टाक्वियो के दूसरे हाफ के स्टॉपेज टाइम के दूसरे मिनट में किये गये गोल की बदौलत कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराकर विश्व कप में अपनी पहली नॉकआउट मैच जीत हासिल करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। सोफी स्टेडियम में चल रहा तनावपूर्ण मैच अतिरिक्त समय की ओर बढ़ता दिख रहा था, तभी यूस्टाक्वियो, जो कुछ मील दूर स्थित एलएएफसी के लिए पेशेवर रूप से खेलते हैं, ने पेनल्टी क्षेत्र के बाहर से एक शानदार वॉली शॉट लगाकर रॉनवेन विलियम्स के नेट के निचले कोने में गेंद पहुंचा दी।

सह-मेजबान कनाडा ने अंतिम मिनटों में मजबूत रक्षात्मक खेल का प्रदर्शन करते हुए बढ़त बनाए रखी और शनिवार को ह्यूस्टन में नीदरलैंड या मोरक्को का सामना करने के लिए आगे बढ़ गया। मैच खत्म होने के बाद कनाडा के मैनेजर जेसी मार्श ने अपने खिलाड़ियों में जोश भरते हुए कहा,आप सब कनाडा के हीरो हैं। इस देश के भावी बच्चों के लिए, जो यह खेल खेलते हैं, आप सब कनाडा के हीरो हैं। आप लोगों की वजह से इस खेल का उज्ज्वल भविष्य है। आपको खुद पर और इस खेल पर गर्व होना चाहिए।

कनाडा ने अपने तीसरे विश्व कप में भाग लेते हुए अपने पहले तीन मैच टोरंटो और वैंकूवर में अपने घरेलू मैदान पर खेले, लेकिन पिछले बुधवार को स्विट्जरलैंड से 2-1 से हारने के बाद उन्हें विश्व कप के मेजबान के रूप में घर से बाहर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के कोच ह्यूगो ब्रूस ने कहा, हम मैच इसलिए हार गए क्योंकि हमारी टीम में ताकत और गति की कमी थी, जब मैं इसकी तुलना अपने प्रतिद्वंदी से करता हूं।

यह एक कठिन मैच था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो हम अपने प्रदर्शन से काफी हद तक संतुष्ट हो सकते हैं। हम निराश हैं, क्योंकि हम जीतना चाहते थे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। हमने जो किया वह अच्छा था, और मैं अपनी टीम से बहुत खुश और गौरवान्वित हूं।

भारतीय हॉकी टीम ने शूटआउट में इंग्लैंड को 3-2 से हराया

लंदन,एजेंसी।

भारतीय हॉकी टीम ने अपने अंतिम एफआईएच प्रो लीग 2025-26 मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोलरहित रहा, जिसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल किया। रविवार को खेले गये मुकाबले के शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास सफलतापूर्वक गोल में बदले। वहीं, शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच प्रो लीग 2025-26 अंकतालिका में 16 मैचों से 19 अंक हासिल किए और नौ टीमों में आठवें स्थान पर रहा। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में चार मैच जीते, पांच ड्रॉ खेले, दो शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और सात मुकाबलों में हार का सामना किया। इससे पहले सप्ताह में बेल्जियम ने 39 अंकों के साथ एफआईएच प्रो लीग 2025-26 का खिताब अपने नाम किया।

इसके साथ ही बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया। भारत अंकतालिका में पाकिस्तान से एक स्थान ऊपर रहा, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हारकर सबसे निचले स्थान पर रहा। मैच की शुरुआत में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम इंग्लैंड ने दबदबा बनाया और भारतीय गोलकीपर मोहित शशिकुमार की कड़ी परीक्षा ली।

इंग्लैंड को शुरुआती पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन सैम वार्ड गोल करने में नाकाम रहे। मोहित ने कई बेहतरीन बचाव कर मेजबान टीम को बढ़त लेने से रोके रखा। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने भी लय पकड़ी। अभिषेक और जरमनप्रीत सिंह ने गोल करने के कुछ अच्छे मौके बनाए, लेकिन इंग्लैंड की रक्षापंक्ति भी मजबूत रही। हाफ टाइम तक स्कोर गोल रहित बराबरी पर था।

तीसरे क्वार्टर के अंतिम चरण में मुकाबले का सबसे अहम मोड़ आया, जब यशदीप सिंह की चुनौती के बाद इंग्लैंड को पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया।

हालांकि, भारतीय टीम ने तुरंत रेफरल लिया और वीडियो रिप्ले में यशदीप का टैकल पूरी तरह सही पाए जाने के बाद अंपायर ने अपना फैसला पलट दिया।

बिजनेस

मारुति सुजुकी ने अपने साथ पांच स्टार्टअप्स को जोड़ा

नई दिल्ली,एजेंसी। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार को घोषणा की कि उसने पांच स्टार्टअप्स को अपने साथ जोड़ा है। ये स्टार्टअप्स एआई और सस्टेनेबिलिटी-आधारित समाधान विकसित करेंगे, जिनका उद्देश्य कंपनी की परिचालन दक्षता ग्राहकों के अनुभव और बिजनेस प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना है।

एक्सिस बैंक के सीएफओ पुनीत शर्मा ने दिया इस्तीफा

मुंबई,एजेंसी। देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने सोमवार को घोषणा की कि उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) पुनीत शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने पेशेवर जीवन के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए यह फैसला लिया है।

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 372 अंक फिसला

मुंबई, एजेंसी।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ने के कारण हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ, और इस तरह घरेलू बाजार में लगातार दो दिनों से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया, जब ऑटो, आईटी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में दबाव के चलते प्रमुख बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी 50 में करीब 0.50 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

बाजार बंद होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 0.48 प्रतिशत यानी 372.10 अंक गिरकर 76,728.37 पर पहुंच गया, तो वहीं एनएसई निफ्टी50 0.46 प्रतिशत या 109.75 अंक फिसलकर 23,946.25 पर बंद हुआ।

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स क्रमशः 0.37 प्रतिशत और 0.62 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टरवार देखें तो निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी मेटल में सबसे ज्यादा बढ़त दर्ज की गई। जबकि इसके विपरीत, ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा 2 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही, निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी आईटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी रियल्टी के शेयरों में 0.9 प्रतिशत से 1.3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई।

निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक, एम एंड एम, टीएमपीवी, इंडिगो और मारुति सुजुकी के शेयर शामिल रहे, जबकि मैक्स हेल्थकेयर, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, कोल इंडिया, एटर्नल, बीईएल और ट्रेंट सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयर रहे। एक बाजार विशेषज्ञ ने बताया कि सोमवार के सत्र में घरेलू शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव भरा कारोबार देखने को मिला। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी पूरे सत्र के दौरान करीब 195 अंकों के दायरे में कारोबार करता रहा।

दिन के पहले हिस्से में बाजार में तेज अस्थिरता रही, जबकि दूसरे हिस्से में कारोबार काफी सीमित दायरे में सिमट गया और निफ्टी केवल 63 अंकों की रेंज में घूमता रहा। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बेयरिश कैंडल बनाई, जो अल्पकालिक कमजोरी का संकेत देती है। तकनीकी दृष्टि से देखें तो निफ्टी अभी भी अपने 20-दिवसीय और 50-दिवसीय एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (ईएमए) के ऊपर कारोबार कर रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि, मोमेंटम इंडिकेटर्स और ऑस्सिलेटर्स यह दर्शा रहे हैं कि फिलहाल बाजार में कंसोलिडेशन का दौर चल सकता है और इंडेक्स सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है।

एक्सपर्ट के अनुसार, आने वाले कारोबारी सत्रों में निफ्टी के लिए 23,850-23,800 का दायरा, जहां 20-दिवसीय और 50-दिवसीय ईएमए मौजूद हैं, महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में काम करेगा। यदि इंडेक्स निर्णायक रूप से 23,800 के नीचे फिसलता है तो गिरावट बढ़कर 23,650 तक जा सकती है।

वहीं दूसरी ओर, 24,070-24,100 का क्षेत्र मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। जब तक निफ्टी इस स्तर को मजबूती से पार नहीं करता, तब तक बाजार में तेजी की रफ्तार सीमित रह सकती है।

गुजरात ने 10 लाख करोड़ के नए निवेश का लक्ष्य रखा

वडोदरा, एजेंसी।

गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने सोमवार को कहा कि राज्य ने अपनी नई 'विकसित गुजरात औद्योगिक नीति-2026' के तहत अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश लक्ष्य के तौर पर रखा है।

वडोदरा में 'वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए संघवी ने कहा कि सरकार सिर्फ रेगुलेटर के तौर पर नहीं बल्कि इंडस्ट्री के पार्टनर के तौर पर काम करेगी। साथ ही, उन्होंने पॉलिसी में स्थिरता और तेजी से काम पूरा करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। अगले पांच सालों में हम 10 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में हम गुजरात के अलग-अलग इलाकों में ये निवेश लाने में सफल होंगे। हर्ष संघवी ने कहा कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी सिर्फ फाइनेंशियल इंसेंटिव (वित्तीय प्रोत्साहन) से कहीं आगे की चीज है, यह एंटरप्रेन्योरशिप और समावेशी विकास पर बहुत जोर देती है।

उन्होंने कहा, इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात सिर्फ इंसेंटिव नहीं है। इंसेंटिव तो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए हैं। हमारी पॉलिसी की सबसे अच्छी बात महिलाओं का सशक्तिकरण है। संघवी ने कहा कि नई पॉलिसी फाइनेंशियल इंसेंटिव से आगे बढ़कर एंटरप्रेन्योरशिप और समावेशी विकास, खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को मौजूदा प्रावधानों के अलावा एक प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज का लाभ मिलेगा।

भारत का औद्योगिक उत्पादन मई में 5.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा

नई दिल्ली,एजेंसी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की वृद्धि दर मई 2026 में सालाना आधार पर 5.1 प्रतिशत रही है। इससे यह बढ़कर 122.7 पर पहुंच गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, बिजली और जल प्रबंधन क्षेत्रों ने प्रमुख योगदान दिया। यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी डेटा में दी गई। खास बात यह है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष को 2011–12 से बदलकर 2022–23 कर दिया है।

यह संशोधित आधार वर्ष के तहत डेटा का दूसरा सेट है। सरकारी डेटा के मुताबिक, मई में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन सालाना आधार पर 5.5 प्रतिशत बढ़ा है। इसे कई उद्योगों में वृद्धि का फायदा मिला है। हालांकि, खनन में मई में सालाना आधार पर 1.6 प्रतिशत की कमी देखी गई है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 16 ने मई 2025 की तुलना में मई 2026 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है।

मई 2026 के दौरान सबसे अधिक सकारात्मक योगदान देने वाले तीन प्रमुख उद्योग समूह में मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर के निर्माण में वृद्धि दर 14.5 प्रतिशत, विद्युत उपकरण के निर्माण में वृद्धि दर 20.8 प्रतिशत और बेसिक मेटल के निर्माण में वृद्धि दर 4.6 प्रतिशत रही।वहीं, बिजली और गैस का उत्पादन 9.9 प्रतिशत और पानी की आपूर्ति में सालाना आधार पर 5.5 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में सालाना आधार पर 12.9 प्रतिशत की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो निवेश गतिविधियों में लगातार तेजी का संकेत है।

किसान सारथी प्लेटफॉर्म से जुड़े करीब 3 करोड़ किसान

नई दिल्ली, एजेंसी।

केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि किसान सारथी प्लेटफॉर्म के साथ 4,767 आईसीएआर वैज्ञानिक और 113 आईसीएआर संस्थान जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 2.95 करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 56.16 लाख महिला लाभार्थी भी शामिल हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए इस एकीकृत डिजिटल कृषि-सलाहकार मंच पर अब तक 19.21 लाख प्रश्नों का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा, किसानों के लिए 351 कृषि उत्पादों से संबंधित 21,900 कृषि सलाह भी जारी की गई हैं।

करीब 2.89 करोड़ किसानों ने अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) जाकर इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया। इनमें से 5.35 लाख किसान कॉल सेंटर के माध्यम से, 21,517 मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए, 2,416 वेब पोर्टल के माध्यम से और 39,193 कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पंजीकरण हुए। सरकार ने बताया कि किसान सारथी की सेवाएं देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 768 जिलों और 6.63 लाख गांवों तक पहुंच चुकी हैं। यह प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम (आईआईडीएस) का उपयोग करता है, जिससे किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच दो-तरफा संवाद संभव हो पाता है। साथ ही, कृषि अनुसंधान से जुड़ी जानकारी सीधे खेतों तक पहुंचाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को समय पर, विश्वसनीय और कई भाषाओं में कृषि संबंधी सलाह उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, मौसम से जुड़े अपडेट और विशेषज्ञों से सीधे परामर्श की सुविधा भी मिलती है। यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसे भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने विकसित और लागू किया है।

सरकार का कहना है कि इन सभी संस्थानों के एक साथ जुड़ने से देश भर में कृषि सलाह का एक मजबूत राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे किसानों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार भरोसेमंद और उपयोगी सलाह मिल रही है।

यह प्लेटफॉर्म किसान कॉल सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मायस्कीम और भाषिनी जैसी प्रमुख राष्ट्रीय सेवाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए किसानों को 610 सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, जिनमें 102 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्रमुख अनाज, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, बागान फसलों और चारा फसलों से संबंधित कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी भी किसानों को दी जाती है। किसान अपनी स्थानीय भाषा में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं और उसी भाषा में सलाह प्राप्त कर सकते हैं। किसान सारथी प्लेटफॉर्म 13 क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषज्ञों से लाइव बातचीत की सुविधा भी देता है।

साथ ही, किसानों के लिए एक ज्ञान भंडार भी उपलब्ध कराता है। इससे कृषि अनुसंधान संस्थानों की पहुंच बढ़ी है और वैज्ञानिक सलाह अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच रही है।

सरकार के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के साथ-साथ कृषि अनुसंधान के व्यावहारिक उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है।

आईने के सामने खुद को देख रो पड़ती थीं अविका

अभिनेत्री अविका गौर ने टीवी स्क्रीन पर मासूम 'आनंदी' बनकर घर-घर में पहचान बनाई, लेकिन एक समय उन्हें अपनी जिंदगी में खुद से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वह आईने में खुद को देखकर रो पड़ती थीं। 30 जून 1997 को मुंबई में जन्मीं अविका गौर ने बहुत छोटी उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। 2007 में उन्होंने 'शश्श्श...कोई है' से छोटे रोल के जरिए टीवी डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2008 में आए शो 'बालिका वधू' से मिली। इस शो में उन्होंने छोटी आनंदी का किरदार निभाया, जो एक बाल विवाह की कहानी पर आधारित था। उनके मासूम अभिनय ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और वह बहुत जल्दी घर-घर में पहचानी जाने लगीं। इसके बाद अविका ने 'ससुराल सिमर का' में रोली का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा लड़की की भूमिका निभाई। यह रोल उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में किया था। इस शो ने भी उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई। इसमें उनकी और अभिनेता मनीष रायसिंघन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया।

टेलीविजन की सफलता के बाद अविका ने फिल्मों की ओर रुख किया। उन्होंने 2009 में 'मॉर्निंग वॉक' और 'पाठशाला' जैसी फिल्मों में काम किया। इसके बाद 2013 में तेलुगु फिल्म 'उय्याला जम्पला' से उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें एसआईआईएमए अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला। यह उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ। उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। एक समय ऐसा भी आया जब अविका अपने शरीर और आत्मविश्वास को लेकर संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने खुद बताया था कि एक समय वह आईने में खुद को देखकर टूट गई थीं और रो पड़ी थीं। उन्हें अपना बढ़ा हुआ वजन और बदलता लुक स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था। इस मानसिक संघर्ष ने उनकी सोच को बदल दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया। उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, नियमित वर्कआउट शुरू किया और अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया। इस बदलाव के जरिए उन्होंने करीब 13 किलो वजन कम किया और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया। उन्होंने कहा था कि पहली बार उन्होंने खुद को वैसे स्वीकार करना सीखा जैसा वह हैं। इसी बीच अविका ने रियलिटी शोज जैसे 'खतरों के खिलाड़ी 9' और दूसरे टीवी प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया। उन्होंने '1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट' जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें वह लीड रोल में नजर आईं।

अली गोनी ने जैस्मिन भसीन के जल्द स्वस्थ होने की दुआ की

टेलीविजन अभिनेता अली गोनी ने अपनी गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री जैस्मिन भसीन के जन्मदिन पर उन्हें भावुक अंदाज में शुभकामनाएं देते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जैस्मिन को गंभीर संक्रमण (इन्फेक्शन) के कारण अपना जन्मदिन अस्पताल में बिताना पड़ा।

अली गोनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए अस्पताल से जैस्मिन की कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। पहली तस्वीर में वह अस्पताल के बेड पर लेटी जैस्मिन को गले लगाते नजर आए, जबकि दूसरी तस्वीर में जैस्मिन व्हीलचेयर पर बैठी दिखाई दीं।

अली ने पोस्ट में लिखा, हैप्पी हैप्पी बर्थडे, जैस्मिन। हम यहां तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए थे, लेकिन जिंदगी की कुछ और ही योजना थी। जन्मदिन की खूबसूरत यादें बनाने की बजाय हम अस्पताल के कमरे में हैं। तुम्हें दर्द में देखना इस पूरे सफर का सबसे मुश्किल पल रहा। तुम्हें फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखने के लिए मैं हर जश्न कुर्बान कर सकता हूं।

उन्होंने आगे लिखा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुशियां, अच्छी सेहत, प्यार और सफलता दे। जल्दी ठीक हो जाओ, आज मेरे दिल में बस यही जन्मदिन की दुआ है। हैप्पी बर्थडे... हमेशा प्यार करता रहूंगा।

एक अन्य पोस्ट में अली गोनी ने बताया कि वह जैस्मिन का जन्मदिन मनाने के लिए दुबई गए थे, लेकिन गंभीर संक्रमण के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा।

इस बीच, हाल ही में अली गोनी ने अपनी शादी की योजनाओं को लेकर भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी थी।

उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, जब शादी करनी होगी, खुद सबको बता दूंगा। मेरे रिश्तेदार भी मेरे पीछे इतने नहीं पड़े, जितना इंस्टाग्राम पर लोग पड़े हैं। अपना-अपना काम करो, खुश रहो और रहने दो।

अली और जैस्मिन लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों की जोड़ी टीवी इंडस्ट्री की चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती है।

विदेश

पाकिस्तान में नशीले पदार्थों की बिक्री बढ़ी: रिपोर्ट

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में हाल के वर्षों में नशीले पदार्थों की ऑनलाइन बिक्री बढ़ी है, क्योंकि डिजिटल लेनदेन की वजह से ड्रग्स तक पहुंचना आसान हो गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में युवा न सिर्फ ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, बल्कि उन्हें बहला-फुसलाकर ड्रग कूरियर भी बनाया जा रहा है।

मास शूटिंग से दहला स्टाड

हैम्बर्ग/स्टाड (जर्मनी), एजेंसी। उत्तरी जर्मनी के स्टाड शहर में सोमवार को मास शूटिंग की भयावह वारदात हुई। गोलीबारी में पांच लोगों के मारे जाने की खबर है। स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है, जबकि पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर पुलिस अभियान जारी है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, घटना स्टाड शहर के डैंकर्सश्ट्रासे इलाके में हुई।

ईरान के राष्ट्रपति का दावा, 'कतर में फंसे 6 अरब डॉलर मिलेंगे जल्द'

तेहरान, एजेंसी।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। दावा किया कि कतर में फंसी ईरान की 12 अरब डॉलर की राशि में से 6 अरब डॉलर जल्द जारी कर दिए जाएंगे। कॉम शहर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बातें कहीं। ईरान की अर्ध-सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर के अनुसार, उन्होंने कहा कि तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को भी राहत मिलेगी।

पेजेश्कियन ने बताया कि शांति समझौते के तहत ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। इसे उन्होंने ईरानी जनता की बड़ी जीत बताया।

पवित्र शहर कॉम की यात्रा के दौरान ग्रैंड अयातुल्ला शोबेरी जंजानी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि कतर में रखे गए कुल 12 अरब डॉलर में से पहले चरण में 6 अरब डॉलर जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाकी 6 अरब डॉलर की वापसी के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

राष्ट्रपति के अनुसार, यह कदम स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता और इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत हुए समझौते का हिस्सा है।

पेजेश्कियन ने हालिया संघर्ष के दौरान ईरानी जनता के जज्बें की सराहना करते हुए कहा कि सर्वोच्च नेता, मंत्रियों, सैन्य कमांडरों, बुद्धिजीवियों और यहां तक कि स्कूली बच्चों की हत्या जैसी घटनाओं के बावजूद देश, सशस्त्र बल और सरकार एकजुट होकर खड़े रहे और राष्ट्र की रक्षा की।

उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजरायल ने आर्थिक दबाव के जरिए ईरान को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जनता के धैर्य और ईश्वर के सहयोग से उनकी योजनाएं सफल नहीं हो सकीं। राष्ट्रपति ने दोहराया कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की मंशा नहीं रखता। यह नीति देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता ने स्पष्ट रूप से घोषित की थी और वर्तमान सरकार भी उसी पर कायम है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम केवल देश की आवश्यकताओं और घोषित नीतियों के अनुरूप ही संचालित होगा। दावा किया कि अंततः अमेरिका ने इजरायल को शांति समझौता स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इजरायल और कुछ विपक्षी समूह अब भी इस समझौते के क्रियान्वयन का विरोध कर रहे हैं।

शी ने लुकाशेंको से भेंट की

बीजिंग, एजेंसी। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने सोमवार सुबह राजधानी पेइचिंग में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की।

इस मौके पर शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और बेलारूस आपसी विश्वास और समर्थन के सच्चे दोस्त हैं, साझा विकास व समृद्धि के लिए अच्छे साझेदार हैं और सभी मौसमों के अनुरूप रणनीतिक साझेदार हैं। चीन-बेलारूस संबंध अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में हुए परिवर्तन की परीक्षा में खरी उतर कर इतिहास में सबसे अच्छे दौर में गुजर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच आपसी राजनीतिक विश्वास चट्टान की तरह मजबूत है और सहयोग में उपलब्धियां हासिल हुई हैं। तथ्यों से साबित हुआ है कि चीन और बेलारूस के बीच व्यापक सहयोग बढ़ाना ऐतिहासिक विकास के रुझान के अनुरूप ही नहीं, दोनों देशों के लोगों के मूल हितों के अनुरूप भी है।

शी चिनफिंग ने कहा कि चीन और बेलारूस को रणनीतिक संपर्क कायम रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों के उच्च स्तर पर विकास बढ़ाना चाहिए। चीन बेलारूस के साथ मानव जाति साझे भविष्य वाले समुदाय का समान निर्माण करने के साथ चार वैश्विक पहलों का कार्यान्वयन करना चाहता है। वहीं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि चीन बेलारूस का सभी मौसमों के अनुरूप रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग व्यापक रूप से बढ़ रहा है। इससे बेलारूस के आर्थिक और सामाजिक विकास को अहम समर्थन मिला। बेलारूस चीन के साथ संबंधों पर बड़ा ध्यान देता है और चीन के साथ रणनीतिक संपर्क व सहयोग बढ़ाना चाहता है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में बेलारूस चीन के साथ घनिष्ठ संपर्क कायम रखना चाहता है, ताकि एक साथ विश्व व क्षेत्रीय शांति, विकास और स्थिरता बढ़ सके।

उत्तर कोरिया ने जापान-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास को बताया 'युद्ध की रिहर्सल'

सोल, एजेंसी।

उत्तर कोरिया ने सोमवार को जापान और अमेरिका के बीच चल रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास की कड़ी आलोचना करते हुए इसे युद्ध की रिहर्सल करार दिया। प्योंगयांग ने जापान को चेतावनी भी दी कि अगर उसने सैन्य गतिविधियों पर विराम नहीं लगाया तो उसके भयावह अंजाम भुगत सकता है।

योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए में सोमवार को प्रकाशित एक संपादकीय में जापान की ग्राउंड सेल्फ-डिफेंस फोर्सेज द्वारा अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के साथ आयोजित 'रिजॉल्यूट ड्रैगन' सैन्य अभ्यास में भागीदारी की आलोचना की गई। इसमें आरोप लगाया गया कि जापान इस तरह अपनी आक्रमण क्षमता को मजबूत कर रहा है।

संपादकीय में कहा गया कि अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाकर जापान क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना रहा है।

इसमें फरवरी में आयोजित अमेरिका-जापान के संयुक्त 'आयरन फिस्ट' सैन्य अभ्यास का भी उल्लेख किया गया। केसीएनए ने यह भी दावा किया कि अप्रैल और मई में अमेरिका के नेतृत्व में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में जापान की पहली भागीदारी के दौरान पड़ोसी देशों पर पूर्व-नियोजित हमला करने की क्षमता के तहत लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया गया था।

अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले में 36 नागरिकों की मौत

काबुल, एजेंसी।

पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए जबकि 163 घायल हो गए। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने दावा किया है कि पक्तिया, पक्तिका और कुनर के पूर्वी प्रांतों में की गई सीमा-पार सैन्य कार्रवाई में व्यापक तबाही हुई है।

तालिबान के उप-प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिक हताहतों का विवरण साझा करते हुए कहा, अब तक उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार, बीती रात हुए हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मृत्यु हो गई, जबकि 163 अन्य घायल हुए हैं। इसके अलावा, तीन आवासीय मकान पूरी तरह नष्ट हो गए। पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई के निशाने पर आए क्षेत्रों का विवरण देते हुए फितरत ने बताया कि पक्तिया प्रांत के चमकनी जिले के मंडोखेल गांव में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने एक नागरिक के घर पर बमबारी की। इस हमले में एक बुज़ुर्ग और एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए।

उप-प्रवक्ता पोस्ट में आगे कहा कि इसके बाद उसी स्थान पर बचाव कार्य में जुटे लोगों को भी निशाना बनाया गया।

उन्होंने कहा, जब स्थानीय निवासी घायलों को बचाने के लिए एकत्र हुए, तो उस स्थान पर दूसरी बार बमबारी की गई, जिससे 28 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई और 158 अन्य घायल हो गए।

बयान के अनुसार, एक अन्य घातक हमला पक्तिका प्रांत के गियान जिले के वालुस्त गांव में हुआ, जहां एक ग्रामीण के घर को निशाना बनाया गया।

फितरत ने कहा, इस हमले में छह लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। वहीं, तीसरा हमला कुनर प्रांत के मनोगई ज़िले के बारोलो गांव में हुआ। फितरत के अनुसार, एक नागरिक के घर पर बमबारी की गई।